सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh
RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 135, नई दिल्ली । शुक्रवार, 26 जुलाई 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

जब तक जीना, तब तक सीखना, अनुभव ही जीवन में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है।

03 आधी दिल्ली में पानी की किल्लत,पानी में बढा- अमोनिया ,जल संयंत्र ठप्प
06 भारतीय शिक्षा प्रणाली: एक जीवंत राष्ट्र का निर्माण
08 सीरवी संस्थान उदयपुर छात्रावास का हुआ भूमि पूजन

दिल्ली में PUC की हड़ताल खत्म, वाहनों के प्रदूषण जांच में मिली बड़ी राहत

अपनी मांगों को लेकर पिछले 10 दिनों से धरने पर बैठे दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने आज अपनी हड़ताल को वापस लेने की घोषणा की है। डीपीडीए के मुताबिक परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव के साथ बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। अभी तक 400 पेट्रोल पंपों पर स्थित 644 पीयूसी बंद चल रहे थे।

नई दिल्ली। दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन (डीपीडीए) ने दिल्ली भर के पेट्रोल पंपों पर स्थित वाहनों के प्रदूषण जांचने के केंद्र (पीयूसी) की हड़ताल को वापस ले लिया है।

15 जुलाई से चल रहा था यह हड़ताल

यह हड़ताल 15 जुलाई से चल रहा था। इसके तहत 400 पेट्रोल पंपों पर स्थित 644 पीयूसी बंद चल रहे थे। यह हड़ताल पीयूसी शुल्क में बढ़ोत्तरी की मांग को लेकर था, लेकिन सरकार इस मामले पर सख्त थी।

परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव के साथ बैठक में फैसला

डीपीडीए के अनुसार परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव के साथ बैठक में यह निर्णय लिया गया। जिसमें तुरंत हड़ताल वापस लेने तथा दिल्ली की आम जनता के हित में पीयूसी संचालन फिर से शुरू करना शामिल है।

बताया गया कि परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव दरों में संशोधन के पहलू पर फिर से विचार करने पर सहमत हुए हैं। डीपीडीए इस संबंध में जल्द एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

दिल्ली परिवहन विभाग के आला अधिकारी ग्रामीण सेवा, इको फ्रेंडली सेवा और फटफट सेवा के वाहन मालिकों को उनके पूराने वाहनों को नए इलैक्ट्रिक वाहनों से बदलने की इजाजत देने में क्यों कर रहे हैं आनाकानी ?

संजय बाटला

नई दिल्ली। भारत देश की आजादी के आस पास से फटफट सेवा, कुछ वर्षों उपरान्त ईको फ्रेंडली सेवा और 2010 सेआरटीवी एवम्ग्रामीण सेवा दिल्ली की जनता को सार्वजनिक सवारी सेवा प्रदान करने वाली श्रेणियो में प्रमुख भूमिका निभाती नजर आती थी। 2020 में कोरोना काल के शुरु होने के साथ ही दिल्ली की सड़को से इन सभी श्रेणियों के वाहन नादारद होते आ रहे हैं और उसका मुख्य कारण है दिल्ली परिवहन विभाग की गलत नीतियां और पालिसी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देश और उपराज्यपाल दिल्ली द्वारा नोटिफाइड आदेश होने के बावजूद दिल्ली परिवहन विभाग ने ई रिक्शा के चलने के लिए प्रतिबंधित सड़को पर भी कभी रोक लगाने का प्रयास नही किया और ना ही दिल्ली की सड़को पर बिना पंजीकरण, बिना इंश्योरेंस, बिना फिटनेस प्रमाण पत्र, बिना वैलिड चालक लाइसेंस के चलने वाले इन ई रिक्शाओं पर पाबंदी लगाने की कोशिश की कारण **किसी से भी छुपा हुआ नही है** इसके अतिरिक्त दिल्ली में स्टेज कैरेज परमिट पर चलने वाले और एक नियम कानून और आदेश में बंधित श्रेणियो में से सिर्फ क्लस्टर और डीटीसी बसों में महिला, मजदूर फ्री सफर की घोषणा कर अन्य श्रेणियों के वाहन मालिको की कमर तोड कर रख दी। कारण यह दो (कलस्टर और डीटीसी) ही एग्रीमेंट के अनुसार ऐसी वाहन सेवा है जिन्हे एक रुपया भी सरकार को एग्रीमेंट कीमत से अधिक नही देना था और **पिंक पास के नाम से दिखाई जाने वाला पूरा पैसा इन्हीं की जेब में आना था।** अर्थ **जनता के बीच सरकार की छवि बनवाना वह भी बिना एक भी पैसा खर्चे किए** जब की अगर यह स्कीम आरटीवी पर भी जो कानूनन लागू होनी चाहिए थी लागू करते तो उन्हे परिवहन विभाग को पिंक पास के तहत घोषित प्रति पास 10 रुपए के हिसाब से देना पड़ता। परिवहन विभाग के आला अधिकारी दिल्ली की जनता के प्रति नही बल्कि दिल्ली सरकार के वोट बैंक और राजस्व इजाफा के प्रति कार्यरत हैं। **इस बात की पुष्टि इससे भी हो जाएगी की मोहल्ले**

के अन्दर जाने और द्वार से द्वार तक सेवा देने के लिए छोटे वाहन ही सम्भव है पर दिल्ली सरकार का पक्ष रखने के लिए मोहल्ला बस सेवा के लिए 9 मीटर की बस को अनुमति दी जो किसी भी हालात में मुख्य सड़को के अलावा कहीं और सेवा प्रदान कर ही नहीं सकतीं। मोहल्ला बस सेवा में 9 मीटर की बस चलाने से अगर किसी को फायदा मिलेगा तो वह मिलेगा परिवहन विभाग और दिल्ली सरकार को ना की जनता को। *दिल्ली की जनता को आज द्वार से द्वार, द्वार से मुख्य सड़को, द्वार से मुख्य बाजारों इत्यादि के लिए सार्वजनिक सवारी सेवा की आवश्यकता है और उसके लिए जनता को जो सुरक्षित, सेवा प्रदान कर सकते है वह है अधिक से 3 सवारी सीटर से 7 सवारी सीटर तक के वाहन और इस में जो पूर्व से चल रही श्रेणियां है वह है

1. आटो तीन पहिया (जिस पर उच्चतम न्यायालय द्वारा 1 लाख की पाबंदी लगाई हुई है,
2. टैक्सी
3. फटफट सेवा,
4. इको फ्रेंडली सेवा,
5. ग्रामीण सेवा

और अन्य सेवाओं के साथ इन्ही सभी सेवाओं को जनहित में चलते रहने के लिए परिवहन विभाग को इन श्रेणियो के मालिको को उनके पूराने वाहनों की जगह नए 6+1 (एल 5) ई वाहन जो दिल्ली में 4 वाहन निर्माताओं के उपल्ब्ध है से **जनहित और जनता को सुरक्षित विश्वसनीय समयानुसार सेवा उपल्ब्ध करवाने और दिल्ली में प्रदुषण पर नियंत्रण के लिए बदलने की इजाजत दे देनी चाहिए थी** पर दिल्ली परिवहन विभाग में कार्यरत आयुक्त और विशेष आयुक्त को दिल्ली और दिल्ली की जनता की नही अपितु किसी और की ही चिंता है जिस कारण इस फाइल को कई महीनों से फुटबाल की तरह इधर से उधर घुमा रहे हैं, **जैसे दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा के प्रति पैनिक बटन के डाटा कलेक्शन सेंटर के शुरु होने की फाइल को रोक कर बैठे हैं।**

कालिंदी कुंज से नोएडा आने वाली एक लेन बंद, कांवड़ यात्रा के कारण ट्रैफिक डायवर्जन लागू

सावन का महीना चल रहा है और ये समय बारिश के साथ ही कांवड़ियों का भी होता है। जो हरिद्वार से जल भरकर अपने घर लौटते हैं। इसी को देखते हुए नोएडा में भी अब कांवड़ियों का जत्था आने वाला है। जिस कारण से प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस भी अपने स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं। कालिंदी कुंज से नोएडा व दिल्ली को जाने वाला एक लेन बंद हो जाएगा।

परिवहन विशेष न्यूज

नोएडा। नोएडा में कांवड़ियों का जत्था बढ़ने लगा है। इस कारण कांवड़ मार्ग पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। आज से कालिंदी कुंज दिल्ली से नोएडा की ओर आने वाली एक लेन को बंद (Kalindi Kunj to Noida Diversion) किया जाएगा। ऐसे में महामाया फ्लाईओवर के बीच यातायात का दबाव एक लेन बंद होने के बाद बढ़ता है।

दिल्ली से दो लेन में आता है ट्रैफिक

अभी दिल्ली से दो लेन में ट्रैफिक आता है। डायवर्जन लागू होने के बाद पुल का एक हिस्सा बंद कर दिया जाता है। ऐसे में वाहन चालकों को निकलने के लिए सिर्फ एक लेन मिलती है। दिल्ली कालिंदी कुंज से ओखला बर्ड सेंचुरी तक वाहन चालक एक लेने में आते हैं।

सेक्टर-16 फिल्म सिटी की ओर जाने वाला मार्ग बंद

अभी सेक्टर-95 फर्नीचर मार्केट के पास निर्माण कार्य के चलते सेक्टर-16 फिल्म सिटी की ओर जाने वाला मार्ग बंद है। इस कारण वाहन चालकों को सेक्टर-37, बोटेनिकल गार्डन, सेक्टर-18 होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाना पड़ रहा है।

इसके अलावा अभी डायवर्जन के कारण चिल्ला रेड लाइट से पक्षी विहार गेट तक मार्ग पर वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। सेक्टर-14ए शनि मंदिर से ओखला बर्ड सेंचुरी होते हुए सिर्फ कांवड़ ले जाने वाले और शिविर लगाने से संबंधित लोगों को छूट है।

चिल्ला बॉर्डर के पास बने स्थायी ट्रैफिक बूथ ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की ड्यूटी निगरानी के लिए लगाई गई है। अभी कालिंदी कुंज, डीएनडी, चिल्ला बॉर्डर, छिजारसी, मॉडल टाउन के पास यातायात कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। कांवड़ का जत्था गुजरने के दौरान ट्रैफिक पुलिसकर्मी यातायात को रोककर कांवड़ियों को रास्ते दिखाने का काम करते हैं।

संस्कारशाला: अनुशासन और जिम्मेदारी का महत्व

प्रियंका श्रीवास्तव

हमारे समाज में, बच्चों की परवरिश और उनके जीवन के अनुभवों का बड़ा महत्व होता है। जब बच्चे अपने माता-पिता से पूछते हैं कि ₹आपने हमारे लिए क्या किया है?₹ तो माता-पिता को यह एहसास दिलाना जरूरी है कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए क्या-क्या किया है। बच्चों को चीजों की कीमत का एहसास कराने के लिए जरूरी है कि उन्हें यह समझाया जाए कि विशेषाधिकार और वंचितता क्या होती है।

हमारे बच्चे, जो कि अक्सर सभी सुविधाओं और वस्त्रों से संपन्न होते हैं, उनके पास जीवन के वास्तविक संघर्षों का अनुभव नहीं होता है। ऐसे में उनके मन में यह सवाल उठ सकता है कि माता-पिता ने उनके लिए क्या किया है। यह जरूरी है कि माता-पिता अपने बच्चों को समय-समय पर, बिना बहस किए, यह एहसास दिलाएं कि उन्होंने उनके लिए कितनी मेहनत और प्रयास किए हैं।

जब हम अपने बच्चों को बिना मांगे सब कुछ प्रदान करते हैं, तो वे चीजों की असली कीमत नहीं समझ पाते। यह महत्वपूर्ण है कि बच्चे यह जानें कि उनके पास जो कुछ भी है, वह माता-पिता की कठिन मेहनत और समर्पण का परिणाम है। उन्हें यह समझाना जरूरी है कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो इन सुविधाओं से वंचित हैं।

इस संदर्भ में, विशेषाधिकार और वंचितता के बीच का अंतर समझाना

अत्यंत महत्वपूर्ण है। बच्चों को यह समझना चाहिए कि विशेषाधिकार का मतलब सिर्फ भौतिक संपत्ति से नहीं है, बल्कि अवसरों और सुविधाओं से भी है। उन्हें यह जानना चाहिए कि दुनिया में कई लोग हैं जो बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं और जिनके पास वे सुविधाएं नहीं हैं जो हमारे बच्चों के पास हैं।

इसलिए, बच्चों को समझाना चाहिए कि उन्हें जो कुछ भी मिला है, उसकी कीमत समझें और उसका सही उपयोग करें। माता-पिता को चाहिए कि वे बच्चों को सिखाएं कि वे अपनी सुविधाओं को साझा करें और वंचित लोगों की मदद करें। उन्हें यह एहसास दिलाना चाहिए कि समाज के सभी लोग एक समान नहीं हैं और हर किसी को मदद की जरूरत हो सकती है।

इस तरह की शिक्षाएं बच्चों में संवेदनशीलता और समर्पण की भावना को बढ़ावा देती हैं। यह उन्हें एक अच्छे इंसान बनने की दिशा में प्रेरित करती हैं। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे बच्चे अपनी सुविधाओं को समझें और समाज में दूसरों की मदद के लिए तैयार रहें।

इस प्रकार, संस्कारशाला के अंतर्गत, बच्चों को विशेषाधिकार और वंचितता का अंतर सिखाना और उन्हें समाज के प्रति जिम्मेदार बनाना अत्यंत आवश्यक है। यह उन्हें न केवल एक अच्छे नागरिक बनने में मदद करेगा, बल्कि उन्हें जीवन में सच्ची खुशी और संतोष भी प्रदान करेगा।

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)
TOLWA
website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com
रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल - 0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण
रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

पर्यावरण पाठशाला: समाज कल्याण के लिए राजनीति और व्यक्तिगत हितों से परे जमीनी कार्यवाही की आवश्यकता : अंकुर शरण

आज हमारा समाज विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहा है, जैसे पार्कों की कमी, सड़क सुरक्षा, पेड़ों की कमी, जल भराव, और नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना। इन सभी मुद्दों को सुलझाने के लिए सिर्फ राजनीति और व्यक्तिगत हितों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। हमें सामुदायिक भागीदारी और स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका को समझते हुए, जमीनी स्तर पर ठोस कदम उठाने की जरूरत है। इस लेख में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के सहयोग से हम अपने समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं।

#VocalForLocalIssues :

स्थानीय निवासी किसी भी समस्या के लिए सबसे अच्छे संसाधन होते हैं। वे समस्या और समाधान दोनों को अच्छी तरह समझते हैं। हर भारतीय को अपनी सोच बदलने की जरूरत है कि ₹हमने कर चुकाया है, यह हमारा काम नहीं है।₹ हमें कुछ जिम्मेदारियां और जवाबदेही स्वीकार करनी चाहिए और संबंधित अधिकारियों को उनके कार्य पर लगाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता, तो सोशल मीडिया और व्यक्तिगत मुलाकातों के माध्यम से मुद्दे को उठाएं।

पार्कों की कमी और हरियाली

आजकल शहरों में हरियाली की कमी और पार्कों का अभाव एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। बच्चों के खेलने के लिए सुरक्षित स्थान नहीं हैं और बुजुर्गों के लिए टहलने के स्थानों की कमी है। हमें स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर पार्कों का विकास करना चाहिए। सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित कर, पौधारोपण अभियानों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे और बुजुर्ग स्वस्थ वातावरण में रह सकें।

सड़क सुरक्षा और यातायात नियम

सड़क दुर्घटनाएं आजकल आम हो गई हैं, जिसमें नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना एक प्रमुख कारण है। हमें स्थानीय प्रशासन और पुलिस के सहयोग से सड़क सुरक्षा अभियान चलाना चाहिए। जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से, लोगों को यातायात नियमों के पालन की आवश्यकता के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। विशेष रूप से नाबालिगों के

लिए वाहन चलाने पर रोक लगाना और उन्हें सुरक्षा नियमों का पालन करना सिखाना महत्वपूर्ण है।

पेड़ और पर्यावरण संरक्षण

हमारे शहरों में पेड़ों की कमी के कारण वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। इसके लिए हमें व्यापक स्तर पर पेड़ लगाने के अभियान शुरू करने चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर नागरिक एक पेड़ लगाए और उसकी देखभाल करे। इस दिशा में कार्य करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे न सिर्फ लोगों को जागरूक करते हैं बल्कि उन्हें अपने पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनाते हैं।

जल भराव और ड्रेनेज की समस्या

मानसून के दौरान जल भराव की समस्या शहरों में आम है, जिससे लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके समाधान के लिए हमें स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर ड्रेनेज सिस्टम में सुधार करना चाहिए। सामुदायिक स्वच्छता अभियान चलाकर, लोगों को जलभराव से बचने के उपायों के बारे में जानकारी देनी चाहिए।

सामाजिक कार्यकर्ताओं की भूमिका

समाज में सामाजिक कार्यकर्ताओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वे न सिर्फ समस्याओं को उजागर करते हैं बल्कि उनके समाधान के लिए भी प्रयासरत रहते हैं। उनके द्वारा किए गए स्वैच्छिक कार्य समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत होते हैं। ऐसे कार्यकर्ता बिना किसी स्वार्थ के समाज के लिए काम करते हैं और समाज को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

समाज की भलाई के लिए हमें राजनीति और व्यक्तिगत हितों से परे जाकर सोचना होगा। हमें स्थानीय समुदायों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर समस्याओं के समाधान के लिए काम करना चाहिए। समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए हर व्यक्ति की भागीदारी आवश्यक है। जब हम खुद वह बदलाव बनेंगे जो हम दुनिया में देखना चाहते हैं, तभी हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकेंगे।

indiangreenbuddy@gmail.com

कोशिश करने के बाद भी बढ़ता जा रहा वजन? 5 हार्मोनल असंतुलन हो सकती है वजह, जाने कैसे

अगर वर्कआउट या डाइट करने के बाद भी आपका वजन तेजी से बढ़ता जा रहा है तो इसकी वजह हार्मोनल इंबैलेंस हो सकता है. आइए जानते हैं कि आखिर वे कौन से हार्मोन्स हैं जो असंतुलित होने पर वजन बढ़ाने का काम करने लगते हैं.

शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने वाला एक केमिकल है जिसे 'हार्मोन' के नाम से जाना जाता है. ये रसायन ग्रंथियों द्वारा उत्पादित होते हैं और रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचते हैं. यह हमारे शारीरिक विकास, मेटाबोलिज़्म, इम्यून रिस्पांस और भावनाओं को प्रभावित करने के साथ-साथ वजन को भी नियंत्रित करने का काम करते हैं. हेल्थलाइन के मुताबिक, हार्मोनल असंतुलन वजन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. यहां हम बता रहे हैं उन प्रमुख हार्मोनल असंतुलनों के बारे में, जो वजन बढ़ाने के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं.

हार्मोन्स, जो वजन बढ़ने की वजह बन सकते हैं

थायरॉयड– अगर थायरॉयड ग्रंथि से कम थायरॉयड हार्मोन का उत्पादन होता है तो इससे मेटाबोलिज़्म धीमा हो जाता है और कैलोरी बर्न करने की प्रक्रिया प्रभावित होती है, जिसकी वजह से वजन बढ़ सकता है.

एंग्जायटी से छुटकारा दिलाने वाले 9 योगासन

इंसुलिन– जब शरीर इंसुलिन का ढंग से उपयोग नहीं कर पाता, तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगता है और शरीर शुगर को फैट में बदलकर स्टोर करने लगता है, जिससे वजन बढ़ सकता है. यह स्थिति डायबिटीज़ टाइप 2 का भी संकेत हो सकती है.

कॉर्टिसोल– कॉर्टिसोल को तनाव हार्मोन भी कहा जाता है जो तनाव की स्थितियों में बढ़ जाता है. जब ये शरीर में काफी मात्रा में बनने लगता है, तो कॉर्टिसोल फैट बढ़ाने लगता है, खासकर पेट के आसपास. इसके बढ़ने से भूख भी बढ़ जाती है.

एस्ट्रोजन– महिलाओं में एस्ट्रोजन का असंतुलन वजन बढ़ने का बहुत बड़ा कारण होता है. प्रेगनेंसी और मेनोपॉज के दौरान इस हार्मोन में काफी तेजी से परिवर्तन होता है. अधिक एस्ट्रोजन फैट को कूल्हों और जांघों के आसपास जमा कर देता है.

लेप्टिन और ग्रेलिन–लेप्टिन हार्मोन भूख को नियंत्रित करता है और शरीर को यह संकेत देता है कि पेट भरा हुआ है. लेकिन जब ये ठीक से नहीं बनता, तो भूख बढ़ सकती है और वजन बढ़ने लगता है. वहीं, ग्रेलिन हार्मोन भूख को बढ़ाता है.

क्या है उपाय–

– हार्मोनल असंतुलन का सही उपाय के लिए डॉक्टर या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से जांच कराएं.

– हार्मोनल असंतुलन को नियंत्रित करने के लिए हेल्दी डाइट प्लान करें.

– रोजाना वर्कआउट, वॉक, रनिंग आदि करें. फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं.

– ध्यान, योग या अन्य तरीकों से तनाव को मैनेज करने का उपाय करें.

– अच्छी नींद हार्मोनल संतुलन बनाए रखने में मदद करती है.

एंजाइटी-डिप्रेशन की वजह बन सकती है बॉडी शेमिंग, खुद पर न होने दें हावी, इन 5 तरीकों से करें अवॉइड

कई बार दोस्त मजाक–मजाक में लोगों की बॉडी को लेकर गलत कमेंट कर देते हैं, जिसका उसके दिमाग पर गहरा असर होता है. बॉडी शेमिंग की वजह से लोग एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं. हालांकि इससे बचने की जरूरत होती है.

नोएडा की एक बैंक में काम करने वाली युवती ने बॉडी शेमिंग और पर्सनल कमेंट्स से परेशान होकर सुसाइड कर ली. आरोप है कि युवती के सहकर्मी उसकी बॉडी को लेकर भद्दे कमेंट करते थे. इससे युवती मानसिक रूप से परेशान हो गई और कई बार उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ा. कई बार परेशानी से निजात पाने के लिए दवाइयों का सहारा भी लेना पड़ा, लेकिन इन सबके बावजूद वह इन सब चीजों से उबर नहीं पाई. यह पहला मामला नहीं है, जब बॉडी शेमिंग की वजह से किसी को जान देनी पड़ी है. बॉडी शेमिंग के ऐसे कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं. सबसे पहले तो एक्सपर्ट से यह जानते हैं कि बॉडी शेमिंग क्या होती है और इसकी वजह से लोगों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है. साथ ही इससे उबरने के तरीके भी जानेंगे.

नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर और साइकेट्रिस्ट डॉ. प्रेरणा कुकरेती ने बताया कि किसी व्यक्ति के शरीर, आकार, वजन, स्किन टोन या अपीयरेंस के बारे में गलत या नेगेटिव कमेंट कर उसकी बेइज्जती करना बॉडी शेमिंग कहलाता है. अक्सर लोग मोटापा, हाइट और कलर कॉम्प्लेक्शन को लेकर बॉडी शेमिंग करते हैं. कई बार लोग किसी की डाइट को लेकर मजाक उड़ाते हैं. बॉडी शेमिंग वर्कप्लेस, दोस्तों के बीच या सोशल मीडिया के जरिए भी की जा सकती है. कई बार लोग खुद भी अपने बारे में इस तरह की नेगेटिव बातें सोचते हैं और उन्हें लगता है कि उनके शरीर का कोई अंग ठीक नहीं है. इसके अलावा भी कई बार लोग अपने आप बॉडी शेमिंग का शिकार होने लगते हैं.

साइकेट्रिस्ट डॉक्टर प्रेरणा ने बताया कि बॉडी शेमिंग की वजह से बच्चे, किशोर और वयस्क सभी बुरी तरह प्रभावित होते हैं. किशोरावस्था में बॉडी शेमिंग की चपेट में आने का खतरा सबसे ज्यादा होता है. बॉडी शेमिंग की वजह से लोगों की मेंटल हेल्थ बुरी तरह प्रभावित होती है. लोग इसकी वजह से स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो सकते हैं. कई बार लोग इसकी वजह से बेहद आक्रामक हो जाते हैं और दूसरों पर जानलेवा हमला कर सकते हैं. जबकि कई मामलों में लोग खुद ही घुटते रहते हैं और आत्महत्या जैसा खौफनाक कदम उठा लेते हैं. यह समाज की बड़ी समस्या है, जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. पैरेंट्स को बच्चों को लेकर सावधान रहना चाहिए और इस तरह की घटनाओं पर नजर रखनी चाहिए.

एक्सपर्ट की मानें तो बॉडी शेमिंग से बचने का सबसे अच्छा तरीका अपने शरीर को एक्सेप्ट करना होता है. अगर आप खुद से प्यार करेंगे, तो लोगों की बातों को इग्नोर करना आसान हो जाएगा और बॉडी शेमिंग के बुरे असर से बच पाएंगे. खुद पर भरोसा करके आप लोगों के नेगेटिव कमेंट्स से बच पाएंगे. अगर चीजें आपके कंट्रोल से बाहर हो रही हों, तो आप इस बारे में अपने पैरेंट्स या करीबी लोगों से बात कर सकते हैं. लोगों के नेगेटिव और गलत कमेंट्स को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए. अगर फिर भी आप बॉडी शेमिंग के असर से बच नही पा रहे हैं, तो आपको साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए. एक्सपर्ट आपको ऐसी कंडीशन से उबरने में मदद कर सकते हैं और इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस पाने में आसानी हो सकेगी.

महिलाओं में चुपके से आती हैं ये 5 'साइलेंट किलर' बीमारियां, ध्यान नहीं दिया तो बन जाएगी बड़ा खतरा...

महिलाओं में भी कई बीमारियां 'साइलेंट किलर' होती हैं. ये बीमारियां शरीर में बढ़ती चली जाती हैं, लेकिन इनके लक्षण जल्दी दिखाई नहीं देते.

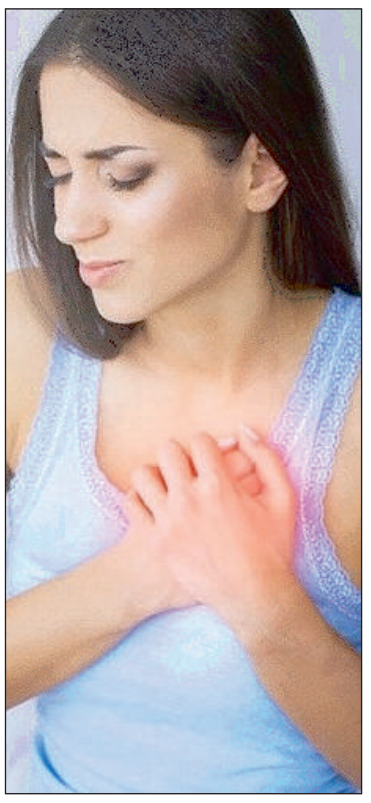

ज्यादातर बीमारियां ऐसी होती हैं जो किसी व्यक्ति के शरीर में बढ़ती चली जाती हैं और उसे इस बात की भनक तक नहीं लगने देतीं. न सिर्फ पुरुषों में बल्कि महिलाओं में भी कई खतरनाक बीमारियां चोरी-छिपे आती हैं. जब तक इनका पता चलता है, तब तक या तो बहुत देर हो चुकी होती है या इलाज करना असंभव हो जाता है. महिलाओं में भी कई बीमारियां 'साइलेंट किलर' होती हैं. ये बीमारियां शरीर में बढ़ती चली जाती हैं, लेकिन इनके लक्षण जल्दी दिखाई नहीं देते और अगर दिखते भी हैं तो इन्हें अक्सर सामान्य समस्या समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है.

आजकल के खराब खानपान और लाइफस्टाइल की वजह से ज्यादातर लोग किसी न किसी बीमारी का सामना कर रहे हैं. आइए जानते हैं कि महिलाओं में कौन-कौन सी बीमारियां 'साइलेंट किलर' होती हैं.

एनीमिया

एनीमिया एक कॉमन प्रॉब्लम है, जो ज्यादा किशोर लड़कियों में देखी जाती है. क्योंकि वे ज्यादातर ऐसे फूड आइटम्स खाती हैं, जिनसे शरीर को ठीक से पोषण नहीं मिल पाता. एनीमिया से बचने के लिए आयरन, विटामिन C और फोलेट से भरपूर भोजन का सेवन किया जाना चाहिए. आयरन से भरपूर आहार में बीन्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, पोल्ट्री, ऑर्गन मीट और सूखे मेवे शामिल हैं. विटामिन C खट्टे फलों, पपीता, पालक और शिमला मिर्च में पाया जाता है. जबकि फोलेट साबुत अनाज, अंडे, मूंगफली, हरी पत्तियों और बीजों में मौजूद होता है.

पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (PCOS) या पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज (PCOD)

इस बीमारी का पता आमतौर पर तब चलता है, जब कोई महिला गर्भवती होने की कोशिश कर रही होती है. ये एक हार्मोनल इंबैलेंस है, जिसका प्रभाव मेटाबोलिक हेल्थ पर पड़ता है. इसके सामान्य दुष्प्रभावों में मोटापा और इंसुलिन रेजिस्टेंस शामिल हैं. इस बीमारी में रिफाइंड कार्ब्स, चीनी से भरपूर भोजन और प्रोसेस्ड फूड से बचने की जरूरत होती है. साबुत अनाज और फलियां इंसुलिन रेजिस्टेंस में काफी मदद करती हैं.

मेनोपॉज

मेनोपॉज एक महत्वपूर्ण हार्मोनल चेंज है, जो सभी महिलाओं में होता है. इसमें फीमेल हार्मोन यानी एस्ट्रोजन कम हो जाता है. दिल की बीमारी के खिलाफ इसकी प्रोटेक्टिव एक्टिविटी भी कम हो जाती है. यह समय नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में जागरूकता बढ़ाने का आह्वान करता है.

दिल की बीमारी

मेनोपॉज के साथ लिपिड में बढ़ोतरी होती है और ब्लड वैसल्स की वॉल्स में बदलाव होता है. इसकी वजह से दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है. दिल से जुड़ी बीमारियों से बचाव के लिए साबुत अनाज, फलियां, ताजे फल और सब्जियां, मेवे और हेल्दी फैट का सेवन करना चाहिए. 30 से 40 मिनट की एक्सरसाइज के साथ लो-सेचुरेटेड फैट, लो-ट्रांस फैट और हाई फाइबर वाला भोजन खाना चाहिए. इससे हृदय रोग को रोकने में काफी मदद मिल सकती है.

बोन हेल्थ

महिलाओं में हड्डियों का स्वास्थ्य यानी बोन हेल्थ 30 के दशक में बिगड़ना शुरू हो जाता है. हड्डियों की मजबूती बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम के सेवन के साथ-साथ एक्सरसाइज करना जरूरी है. डेयरी प्रोडक्ट कैल्शियम का सबसे अच्छा सोर्स माने जाते हैं, जैसे दूध, दही या पनीर आदि. आप शाकाहारी सोया दूध भी चुन सकते हैं. ये शरीर को प्रोटीन और फास्फोरस प्रदान करते हैं, जिनसे हड्डियों के निर्माण में मदद मिलती है।

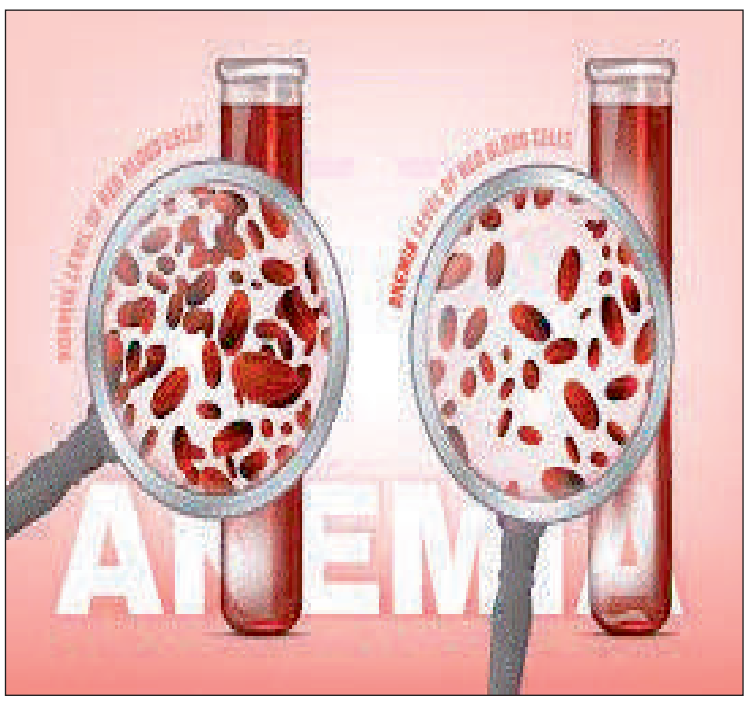

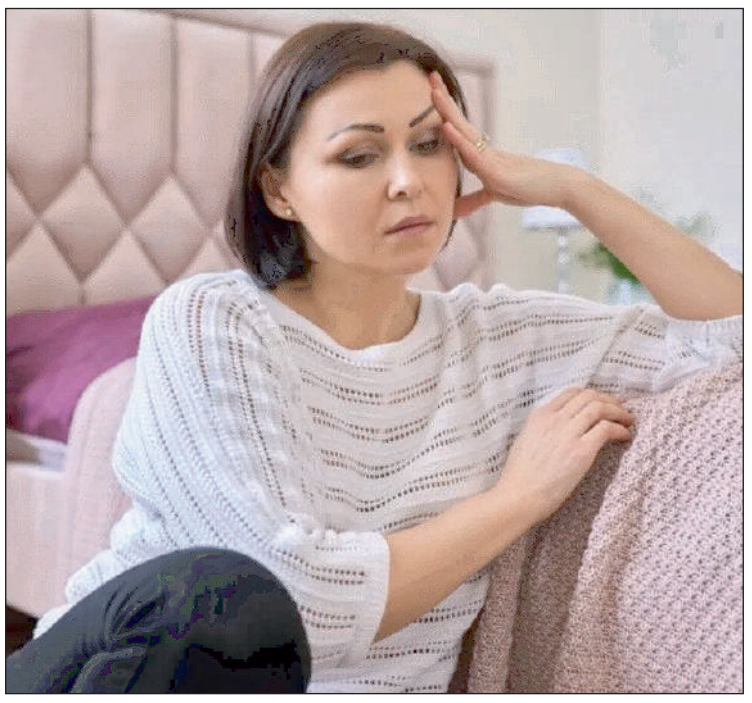

महिलाओं में ग़ैर-संक्रामक बीमारियों का बढ़ता प्रचलन!

रोकथाम, जल्दी पता लगाना और इलाज ग़ैर-संक्रामक बीमारियों से होने वाली मौतों में महत्वपूर्ण कमी लाने के लिए आवश्यक है.

ग़ैर-संक्रामक बीमारियां यानी (NCD) दुनिया भर में सालाना 4 करोड़ 10 लाख या कुल मौतों में से 74 प्रतिशत के लिए ज़िम्मेदार हैं. NCD से जुड़ी मौतों में से 77 प्रतिशत निम्न या मध्यम आमदनी वाले देशों में होती हैं. ग़ैर-संक्रामक बीमारियों से हर साल होने वाली आधी से ज़्यादा मौतें या 1 करोड़ 79 लाख मौतें दिल से जुड़ी बीमारियों से होती हैं. इसके बाद कैंसर (93 लाख), फेफड़े से जुड़ी बीमारी (41 लाख) और डायबिटीज़ (20 लाख मौतें जिनमें डायबिटीज़ की वजह से होने वाली किडनी की बीमारी से मौतें शामिल हैं) हैं. ग़ैर-संक्रामक बीमारियों से जुड़ी मौतों में से जो 80 प्रतिशत से ज़्यादा मौतें समय से पहले होती हैं वो इन चार तरह की बीमारियों के कारण होती हैं.

महिलाएं एवं लड़कियां विशेष रूप से जोख़िम का सामना कर रही हैं क्योंकि मरने वाली हर तीन महिलाओं और लड़कियों में से क़रीब-क़रीब दो की मौत NCD से होती है. इसका मतलब है कि हर साल 1 करोड़ 68 लाख महिलाओं की मृत्यु गैर-संक्रामक रोगों से होती है.

महिलाएं एवं लड़कियां विशेष रूप से जोख़िम का सामना कर रही हैं क्योंकि मरने वाली हर तीन महिलाओं और लड़कियों में से क़रीब-क़रीब दो की मौत NCD से होती है. इसका मतलब है कि हर साल 1 करोड़ 68 लाख महिलाओं की मृत्यु गैर-संक्रामक रोगों से होती है. पिछले तीन दशकों के दौरान निम्न और मध्यम आमदनी वाले देशों में महिलाओं की सेहत से जुड़ी समस्याओं में काफ़ी बदलाव आ चुका है. NCD, जिन्हें पहले अमीरों की बीमारी माना जाता था, अब विकासशील और विकसित-दोनों प्रकार के देशों में महिलाओं के बीच मौत और विकलांगता का सबसे बड़ा कारण है. लैंसेट के मुताबिक़, जिन 186 देशों और क्षेत्रों में अध्ययन किया गया है उनमें से 164 (88 प्रतिशत) में महिलाओं और 165 (89 प्रतिशत) में पुरुषों के 70 वर्ष से कम उम्र में संक्रामक, मां से जुड़ी, नवजात और पोषण संबंधी बीमारियों को मिलाकर होने वाली कुल मौतों के मुक़ाबले NCD से मरने की ज़्यादा आशंका है.

आंकड़ा 1: अलग-अलग उम्र और लिंग के अनुसार विश्व में ग़ैर-संक्रामक बीमारियों का बोझ

उपर्युक्त आंकड़े से पता चलता है कि पुरुषों के मुक़ाबले महिलाओं में ग़ैर-संक्रामक बीमारियां होने की आशंका ज़्यादा है और जैसे-जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है, उनकी सेहत में गिरावट आती है. हर साल महिलाओं की कुल मौत में अकेले दिल से जुड़ी बीमारियों का योगदान 35 प्रतिशत (तीन में से एक मौत) है लेकिन इसके बावजूद इनका ठीक से निदान या उपचार नहीं होता है. एक अनुमान के मुताबिक़ 2045 तक 2017 के मुक़ाबले 20 से 79 साल की उम्र की 30 करोड़ 80 लाख ज़्यादा महिलाओं को डायबिटीज़ होगा. ये बीमारियां महिलाओं और लड़कियों के बीच तीन में से दो मौतों के लिए ज़िम्मेदार होंगी और उनमें मृत्यु और अपंगता का मुख्य कारण हैं.

महिलाएं एवं लड़कियां, विशेष रूप से निम्न और मध्य आमदनी वाले देशों में रहने वाली, अक्सर संक्रामक और ग़ैर-संक्रामक बीमारियों के साथ-साथ प्रजनन से जुड़े स्वास्थ्य की समस्याओं के तिगुने बोझ का अनुभव करती हैं. NCD की वजह से ख़राब सेहत और मृत्यु समाज में महिलाओं की सामाजिक-सांस्कृतिक स्थिति को जोख़िम में डालती हैं और जीवन भर उनके स्वास्थ्य एवं विकास को प्रभावित करती हैं. महिलाएं एवं लड़कियां को डिप्रेशन और पोस्ट-ट्रॉमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होने का ख़तरा ज़्यादा है और इन दोनों ही बीमारियों का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर दीर्घकालीन नकारात्मक असर पड़ता है.

महिलाओं एवं लड़कियों की केवल व्यक्तिगत सेहत के आगे भी इन बीमारियों का उनके ऊपर काफ़ी असर होता है. मौजूदा समय में मानव जनसंख्या में महामारी विज्ञान से जुड़ी रिसर्च और आनुवंशिक बदलाव की प्रक्रिया की बेहतरीन जानकारी से पता चलता है कि जन्म से पहले की घटनाएं डायबिटीज़ और दूसरी ग़ैर-संक्रामक बीमारियों के विकसित होने में योगदान कर सकती हैं. कुपोषण, देर से शारीरिक एवं मानसिक विकास और वयस्क होने पर ग़ैर-संक्रामक बीमारियां, जिनमें डायबिटीज़ और दिल से जुड़े रोग शामिल हैं, कुपोषित मां के गर्भ से पैदा होने से जुड़े जोख़िम हैं. बदनामी और सामाजिक नियमों के कारण अक्सर तंबाकू खाने, हानिकारक शराब पीने, ख़राब भोजन, शारीरिक रूप से निष्क्रियता और अंदरुनी एवं आस-पास के प्रदूषण से जोख़िम पुरुषों एवं लड़कों के मुक़ाबले महिलाओं एवं लड़कियों में अलग होता है. दुनिया में लगभग 37 प्रतिशत वयस्क पुरुष एवं 9 प्रतिशत वयस्क महिलाएं धूम्रपान करती हैं.

मज़बूत स्वास्थ्य नीति

पुरुषों एवं महिलाओं के बीच NCD से जुड़े जोख़िम अलग-अलग होते हैं. ज़्यादा वज़न या मोटापा स्वास्थ्य से जुड़ी एक गंभीर चिंता है और ये कई तरह के ग़ैर-संक्रामक रोगों से जुड़ा है. बीमारी, अपंगता और मौत का ज़्यादा जोख़िम इसके साथ जुड़ा है. कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों में बढ़ोतरी, जैसे कि कोरोनरी हार्ट बीमारी, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, टाइप-2 डायबिटीज़ और कई तरह के कैंसर, जिनमें मासिक धर्म समाप्त होने के बाद महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर, गर्भाशय का कैंसर, कोलन एवं किडनी का कैंसर शामिल हैं, मौत के लिए बड़े जोख़िम के कारक हैं. मोटापा और शारीरिक निष्क्रियता जैसे जोख़िमों के कारण सामान्य रूप से पुरुषों के मुक़ाबले महिलाओं को NCD से जुड़ा ख़तरा ज़्यादा है. इसकी वजह ये है कि मोटापा और शारीरिक निष्क्रियता पुरुषों की तुलना में महिलाओं में आम तौर पर ज़्यादा देखी जाती हैं.

NCD के कारण स्वास्थ्य देखभाल की लागत में बढ़ोतरी होती है, उत्पादकता को नुक़सान होता है और बेतहाशा खर्च होता है. दुनिया भर में महिलाओं के बीच ग़रीबी ज़्यादा है और वो NCD का इलाज कराने में सक्षम नहीं होती हैं.

महिलाओं की सेहत का असर उनके बच्चों की सेहत पर भी पड़ता है. कुपोषित मां से पैदा बच्चों में कुपोषण, जन्म के समय कम वज़न और बड़े होने पर NCD के प्रति ज़्यादा संवेदनशीलता का जोख़िम होता है. इसलिए मां की बेहतर सेहत भविष्य की पीढ़ी के लिए भी महत्वपूर्ण है.

NCD को सतत विकास के लिए 2030 के एजेंडा में महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य की चिंता के रूप में स्वीकार किया जाता है. सतत विकास लक्ष्य (SDG) 3 के टारगेट 3.4 में 2030 तक NCD से जुड़ी मौतों की संख्या में एक-तिहाई कमी का आह्वान किया गया है. 2015 के स्तर की तुलना में 30 और 70 साल की उम्र के बीच कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों, सांस की बीमारियों और डायबिटीज़ से मरने की आशंका में एक-तिहाई कमी के साथ SDG 3 के टारगेट 3.4 को 35 देशों (19 प्रतिशत महिलाओं और 16 प्रतिशत पुरुषों) में पूरा कर लिया जाएगा।

दिल्ली मेट्रो में उपद्रव मचाने को लेकर हुई 1600 से अधिक लोगों पर कार्रवाई, पिछले साल के मुकाबले हुई बढ़ोतरी

दिल्ली मेट्रो में उपद्रव मचाने की घटनाएं पिछले साल के मुकाबले इस साल तीन फीसदी बढ़ गई है। डीएमआरसी ने अप्रैल से जून के दौरान मेट्रो परिसर में रील बनाने सहित उपद्रव करने के लिए 1600 से अधिक लोगों पर कार्रवाई की है। इसमें रील बनाने वाले लोगों की जानकारी अलग से उपलब्ध नहीं है। मेट्रो ने कहा कि उसके पास सीसीटीवी के जरिए नजर रखने की प्रणाली है।

नई दिल्ली। डीएमआरसी ने मेट्रो परिसर में रील बनाने समेत उपद्रव मचाने के लिए 1,600 से अधिक लोगों पर कार्रवाई की है। अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि डीएमआरसी ने अप्रैल से जून के दौरान मेट्रो परिसर में रील बनाने सहित उपद्रव करने के लिए 1,600 से अधिक लोगों पर कार्रवाई की है, जो एक साल पहले की इसी अवधि से तीन प्रतिशत अधिक है।

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि केवल रील बनाने के लिए यात्रियों को दंडित करने की गणना उपलब्ध नहीं है। उपद्रव पैदा करने में ट्रेन के फर्श पर बैठना और ट्रेन के अंदर खाना खाने जैसे अपराध भी शामिल हो हैं। आंकड़ों के मुताबिक, मेट्रो रेलवे (संचालन और रखरखाव) अधिनियम की धारा 59 के तहत उपद्रव पैदा करने के लिए 1,647 दंड जारी किए गए। पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह संख्या 1,600 थी।

इस साल DMRC ने की अधिक कार्रवाई

डीएमआरसी ने अप्रैल, मई और जून में क्रमशः 610, 518 और 519 कार्रवाई की जानकारी जारी किए। आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले वर्ष में यही संख्याएं 528, 485 और 587 थीं। डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक विकास कुमार ने पीटीआई को बताया कि उन्होंने मेट्रो परिसर में उपद्रव मचाने के लिए लोगों को दंडित किया है।

दंडित करने से लोग ऐसा करने से बचेंगे: DMRC

उन्होंने कहा, ₹हम अपनी पूरी मशीनरी का उपयोग करते हैं ताकि मेट्रो परिसर में इस तरह की घटनाएं न हों। अगर कोई मेट्रो परिसर में उपद्रव करता है तो हमारे पास दंड देने का प्रावधान है और हम उन्हें दंडित करते हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है और जितना अधिक आप ऐसा करते रहेंगे, उतना ही अधिक लोग ऐसी गतिविधियों को करने में हतोत्साहित होंगे।"

हम सीसीटीवी के जरिए लोगों पर रखते हैं नजर: DMRC

उन्होंने कहा, "लेकिन हमारे पास हर कोने की जांच करने के लिए पर्याप्त जनशक्ति नहीं है। अगर हमारे पास एक दिन में 67 लाख यात्री हैं, तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों की निगरानी करना आसान नहीं है। हमारे पास सीसीटीवी निगरानी है जिसके माध्यम से हमें परिसर में क्या हुआ का पता चल जाता है।"

डीएमआरसी ने कई मेट्रो स्टेशनों पर पोस्टर भी लगाए हैं, जिसमें यात्रियों को रील बनाने और असुविधा पैदा करने से रोका गया है। अप्रैल में, ट्रेन के अंदर दो महिलाओं द्वारा एक-दूसरे पर रंग लगाने का वीडियो ऑनलाइन सामने आने के बाद डीएमआरसी ने दिल्ली पुलिस से गहन जांच करने को कहा। होली से पहले सामने आए इस वीडियो की यात्रियों के एक बड़े वर्ग ने आलोचना की थी।

सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल को झटका, न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ी

आबकारी नीति घोटाला से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामले में आज सीबीआई केस में न्यायिक हिरासत खत्म होने पर उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। जहां कोर्ट ने सीबीआई की मांग पर अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आठ अगस्त तक बढ़ा दी है।

नई दिल्ली। आबकारी नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आठ अगस्त तक बढ़ा दी है। बता दें कि न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर केजरीवाल को आज गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया था।

सीबीआई ने 26 जून को किया था गिरफ्तार

केजरीवाल वर्तमान में सीबीआई व ईडी मामले में न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। मनी लॉड्रिंग मामले में ईडी ने 21 मार्च और भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई ने 26 जून को गिरफ्तार किया था।

मनी लॉड्रिंग मामले में मिल चुकी है अंतरिम जमानत

उल्लेखनीय है कि अरविंद केजरीवाल को मनी लॉड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है और सीबीआई मामले से जुड़ी जमानत याचिका दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष लंबित है। सीबीआई ने आबकारी नीति मामले से जुड़ी अनियमितताओं के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री को 'मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक' बताया है। एजेंसी ने दावा किया है कि आप के पूर्व मीडिया प्रभारी और केजरीवाल के करीबी सहयोगी विजय नायर कई शराब उत्पादकों और व्यापारियों से संपर्क में थे। उधर, कोर्ट ने मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता के. कविता की न्यायिक हिरासत 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। दोनों वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए थे। इसके साथ ही केजरीवाल को लेकर ईडी की ओर से दाखिल सातवें पूरक आरोपपत्र पर भी आज सुनवाई होनी है।

मनीष सिसोदिया और के. कविता को फिर लगा झटका, अदालत ने 31 जुलाई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत

आप नेता व दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और के. कविता को एक बार फिर से झटका लगा है। अदालत ने दोनों की न्यायिक हिरासत 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। बताया गया कि दोनों वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे। ऐसे में दोनों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पढ़िए पूरा अपडेट।

नई दिल्ली। दिल्ली शराब नीति मामले में अदालत ने पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, बीआरएस नेता के. कविता की न्यायिक हिरासत 31 जुलाई तक बढ़ाई। दोनों वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे।

इससे पहले 26 तक बढ़ाई थी न्यायिक हिरासत

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत 26 जुलाई तक बढ़ाई थी। वहीं कोर्ट ने बीआरएस नेता के. कविता के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लिया था। कोर्ट ने निर्देश दिया था कि के. कविता को 26 जुलाई को दोपहर दो बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाए।

उधर, मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि 22 जुलाई को खत्म हो रही थी। इस कारण उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। इससे पहले कोर्ट ने 15 जुलाई को सुनवाई करते हुए सिसोदिया को 22 जुलाई तक की कस्टडी में भेजा था।

सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका दो बार हो चुकी खारिज

बता दें कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार गिया गया था। सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका दो बार सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी है और तीसरी बार सिसोदिया का मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है।

के. कविता को AIIMS में किया गया था भर्ती

के.कविता का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। स्त्री संबंधी बीमारी की जांच के लिए उन्हें बीते गुरुवार को अखिल भारतीय युर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) रेफर किया गया था। इससे पहले कविता को तेज बुखार होने पर दीनदयाल उपाध्याय (DDU) अस्पताल ले जाया गया था।

आधी दिल्ली में पानी की किल्लत, पानी में बढा- अमोनिया , जल संयंत्र ठप्प

परिवहन विशेष न्यूज

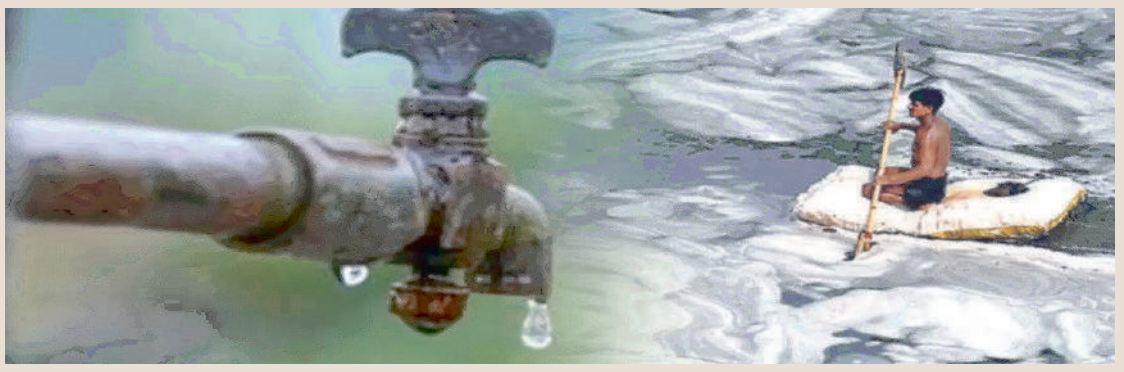

एसडी सेठी। राजधानी दिल्ली में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। अब तक पानी के लिए हरियाणा से गुथ्थम गुथ्था चल रही थी। जल मंत्री ने सत्याग्रह तक कर डाला। लेकिन हरियाणा का दिल नहीं पसीजा, अलबत्ता सत्याग्रह से इन्द्र देव जरूर प्रसन्न हो गए। और पूरी दिल्ली को ही जलमग्न कर दिया। अब आलम ये है कि आधी दिल्ली वालों के नलों में पानी की एक बूंद तक नहीं टपक रही है। लोगों में पानी की किल्लत को लेकर पिछले दो-तीन दिन से हाहाकार मचा हुआ है। इस बावत मुल्तानी ढांढा- पहाडग़ंज के निवासी, अशोक मल्होत्रा ने बताया कि पिछले तीन दिनों से नल सूखे पडे है। जिसकी वजह से नहाने-धोने से लेकर खाने पीने तक के लाले पड गए है। उन्होने बताया कि इस बावत दिल्ली जल बोर्ड के झंडेवालान स्थित दफ्तर में फोन करने पर कोई जवाब देकर राजी नहीं है। पानी ना होने के चलते बार-बार जल बोर्ड के कार्यालय में दम्बिश देने के बाद डीजेबी से एक मैसेज भेजकर अपनी ड्यूटी पूरी कर खामौशी पकड ली है। तीन दिन बाद मैसेज भेजकर बताया गया है कि यमुना नदी वजीराबाद में हाई लेवल पर पल्यूटेड अमोनिया मिक्स पानी आने की वजह से वजीराबाद का वाटर वर्कस ने काम करना बंद या थोडा कर दिया है। लिहाजा पानी की सप्लाई ठप हो गई है। संयंत्र ठप के चलते पानी न आने वाले दिल्ली के प्रभावित इलाको में मजनू का टीला, विधान सभा, राजघाट, प्रेस एरिया, एनडीएमसी, हंस भवन, आईटीओ, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, डिफेंस कॉलोनी, दक्षिण दिल्ली, साउथ एक्सटेंशन, वजीराबाद स्टाफ क्वार्टर, सिग्नेचर ब्रीज, एलएनजेपी अस्पताल, WHO, आईपी एस्टेट, जेजे क्लस्टर भैरो रोड, चिडिया घर, वजीराबाद विलेज, इनमास आर्मी, तिमारपुर पुर, भारत नगर, गोपाल पुर, एसएफएस फ्लेट गुजंरावाला, माडल टाउन, आजाद पुर, शालीमार बाग, वजीर पुर इंडसट्रियल एरिया, लॉरेंस रोड, केशव पुरम, पंजाबी बाग, मुखर्जी नगर, निरंकारी कॉलोनी, जीटीबी अस्पताल, किंग्जवे कैंप, आजाद पुर विलेज, इंदिरा नगर, आदर्श नगर, शांतिवन, ISBT, Gpo, निगम बोधघाट, हनुमान मंदिर यमुना बाजार, आसफ अली रोड, रामलीला ग्राउंड, दिल्ली गेट, सुभाष पार्क, दरिया गंज, गुलाबी बाग, पंजाबी बाग, जहांगीर पुरी, आदर्श नगर, इंदिरा नगर, बुराडी, मॉडल टॉउन, बुराडी, गुलाबी बाग, पंजाबी बाग, मूलचंद, साउथ एक्सटेंशन, मुखर्जी नगर, समेत पूर्वी दिल्ली, उत्तर दिल्ली, और दक्षिण दिल्ली, पश्चिम दिल्ली, के इलाके बिन पानी सूने हो गए। बता दे कि दिल्ली जल बोर्ड अब-तक मीडिया से पानी की किल्लत को लेकर छिपाए बैठा है। यमुना नदी में अमोनिया केमिकल के मिलने से वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट ठप्प हो गया है। इतने बडे लेवल पर प्रभावित इलाकों से अभी तक जल मंत्री आतिशी ने बयान देने की जुर्रत तक नहीं समझी। ना ही इन इलाको में पानी के टैंकर ही भेजे गए हैं। पहाडग़ंज के रहने वाले सोनू, सागर, सुरभि ने झल्लाहाते हुए बताया कि हैरत की बात है कि पानी की परेशानी झेल रही दिल्ली की आधी आबादी को अब तक कोई अपडेट नहीं है कि पानी की सप्लाई कब तक चालू हो जाएगी। इस बावत इस संवाददाता ने दिल्ली जल बोर्ड कंट्रोल रूम के फोन नंबर-1916 पर कई बार फोन करने पर भी किसी ने रिसीव नहीं किया। इमरजेंसी कॉल हैल्प। लाइन का ये हाल है।

नोएडा एयरपोर्ट के लिए रेलवे कनेक्टिविटी पर जोर, रुंधी और चोला के बीच बनेगा 61 किमी लंबा नया रूट

नोएडा एयरपोर्ट के लिए रेलवे कनेक्टिविटी पर बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। इसी क्रम में हरियाणा के रुंधी रेलवे स्टेशन और उत्तर प्रदेश के चोला रेलवे स्टेशन के बीच नया रूट बिछेगा। इसकी लंबाई 61 किलोमीटर होगी। यमुना प्राधिकरण इसे अपने मास्टर प्लान में शामिल करेगा। रेलवे इस नए रूट के लिए परियोजना तैयार करने पर काम कर रहा है।

ग्रेटर नोएडा। नोएडा एयरपोर्ट की रेलवे कनेक्टिविटी के लिए हरियाणा के रुंधी रेलवे स्टेशन और उत्तर प्रदेश के चोला रेलवे स्टेशन के बीच प्रस्तावित रूट को यमुना प्राधिकरण अपने मास्टर प्लान में शामिल करेगा। प्राधिकरण ने इसके लिए संस्तुति दे दी है। इसके साथ ही रेलवे ने नए रूट के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का काम शुरू कर दिया है।

61 किमी लंबा है रूट

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रेलवे कनेक्टिविटी के लिए रेलवे मंत्रालय ने व्यावहारिकता रिपोर्ट तैयार कराई थी। दिल्ली मुंबई रेलवे रूट पर हरियाणा में रुंधी रेलवे स्टेशन से दिल्ली हावड़ा रेलवे रूट के चोला रेलवे स्टेशन के बीच 61 किमी लंबे नया रूट तैयार कर एयरपोर्ट को कनेक्टिविटी तैयार की गई।

यह रूट एविएशन हब में किशोरपुर गांव के नजदीक से गुजरने के कारण यीडा ने यह कहते हुए बदलाव की मांग की थी कि इससे एविएशन हब दो हिस्सों में बंट जाएगा। यीडा के सेक्टरों की कनेक्टिविटी भी प्रभावित होगी।

रूट का 10 किमी हिस्सा होगा भूमिगत

ओएसडी शैलेंद्र भाटिया ने बताया कि एविएशन हब के दो हिस्सों में बंटने से बचाने के लिए रेलवे रूट के 61 किमी में से दस किमी हिस्से को भूमिगत बनाया जाएगा। यह नोएडा एयरपोर्ट पर बनने वाले भूमिगत जीटीसी से होकर गुजरेगा।

दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा रेलवे रूट से आने वाले यात्री सीधे नोएडा एयरपोर्ट के टर्मिनल पर पहुंच सकेंगे। नए रूट पर यात्री गाड़ियों के साथ ही मालगाड़ी का भी संचालन होगा। इससे कार्गो टर्मिनल पर माल की ढुलाई भी संभव होगी। जीटीसी पर ही नमो भारत रेल का स्टेशन भी होगा। इसके साथ ही बस कनेक्टिविटी भी होगी।

यीडा के सेक्टरों से होकर गुजरेगा रूट

रुंधी और चोला के बीच बनने वाला रूट यीडा के सेक्टरों से होकर गुजरेगा। कार्गो टर्मिनल के नजदीक यीडा के मास्टर प्लान 2041 में मल्टी परपज यूज के लिए सेक्टर प्रस्तावित हैं। इन सेक्टर में खासतौर से लाजिस्टिक एवं वेयर हाउसिंग संबंधित गतिविधियां होंगी। यमुना एक्सप्रेस वे और यमुना नदी को पार करते हुए यह रूट हरियाणा में प्रवेश करेगा।

रुंधी व चोला के बीच रेलवे रूट पर यमुना प्राधिकरण से संस्तुति कर दी है। प्राधिकरण इसे अपने मास्टर प्लान 2041 में शामिल करेगा। रूट के लिए रेलवे डीपीआर तैयार कर रहा है। इसके बाद जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी।

शैलेंद्र भाटिया, ओएसडी यीडा

दिल्ली सरकार शहरों की तरह गांवों में भी हर मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है : गोपाल राय

सुषमा रानी

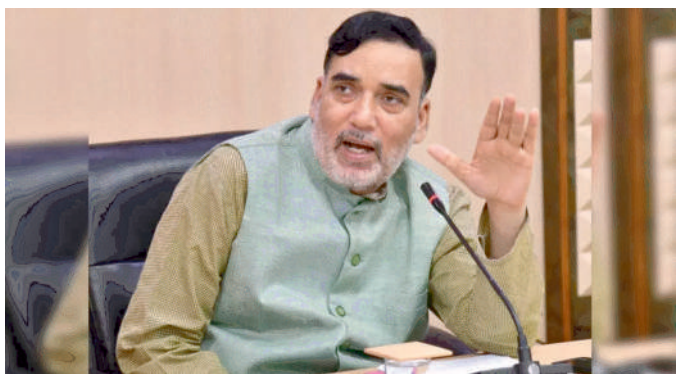

नई दिल्ली। दिल्ली के विकास मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में गुरुवार को दिल्ली के गाँवों के विकास कार्यो को गति देने के लिए दिल्ली सचिवालय में विकास विभाग, एमसीडी और आईएंडएफसी के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। विकास मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली के गांवों के विकास से संबंधित 455 करोड़ की 318 परियोजनाओं को ग्राम विकास विभाग ने स्वीकृति दे दी है। आईएंडएफसी एवं एमसीडी के अधिकारियों को दिल्ली के गांवों के विकास कार्यो से सम्बंधित परियोजनाओं और लंबित प्रस्तावों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को एक सप्ताह के भीतर गांवों के विकास से संबंधित कार्यो पर एक्शन टेकन रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।

विकास मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली के गांवों में विकास सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड का गठन किया था। इस बोर्ड का मुख्य उद्देश्य दिल्ली के गांवों में हर तरह की मूलभूत सेवाएं सुनिश्चित करना है। इसी सन्दर्भ में आज दिल्ली के गांवों से संबंधित विकास कार्य में तेजी लाने के लिए दिल्ली सचिवालय में संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। बैठक के दौरान चल रही परियोजनाओं एवं लंबित परियोजनाओं की समीक्षा की गई और आईएंडएफसी एवं एमसीडी के अधिकारियों को निर्देश दिया कि ग्राम विकास से संबंधित कार्य को तय सीमा के भीतर पूरा करें।

उन्होंने बताया कि गांवों के विकास से सम्बंधित 455 करोड़ की 318 परियोजनाओं को ग्राम विकास बोर्ड विभाग ने मंजूरी दे दी है। उन्होंने आईएंडएफसी एवं एमसीडी के अधिकारियों को जल्द टेंडर करने का निर्देश दिया है, ताकि गांवो के विकास कार्य जल्द पूरा किया जा सके।

राजधानी के गांवों में विकास सुनिश्चित करने के लिए पिछली बोर्ड मीटिंग में दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड ने जिन योजनाओं को मंजूरी दी थी, इसी के संदर्भ में यह समीक्षा बैठक की गई। दिल्ली के विकास मंत्री गोपाल राय ने कहा कि केजरीवाल सरकार गांवों में सड़कों, पार्कों, नालियों और बहुउद्देशीय सामुदायिक केंद्रों की स्थिति में सुधार करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। विकास विभाग से जुड़े इन विकास कार्यों को सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, एमसीडी के माध्यम से किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि केजरीवाल सरकार शहरी क्षेत्रों में रहने वाले दिल्ली के लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, एक सप्ताह तक बिहार और असम जाने वालों को होगी परेशानी

अगर आप एक शहर से दूसरे शहर या गांव आने-जाने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं तो यह जानकारी आपके काम की है। दरअसल मुरादाबाद मंडल में राजघाट और नरोरा यार्ड में इंटरलाकिंग का काम चल रहा है। इससे ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है। साथ ही कई ट्रेनों की टाइमिंग में भी देरी हो सकती है।

नई दिल्ली। अगले एक सप्ताह तक सहरसा, मोतिहारी और असम जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि मुरादाबाद मंडल में राजघाट और नरोरा यार्ड में इंटरलाकिंग का काम चल रहा है जिससे इस रेलखंड पर ट्रेनों की आवाजाही बाधित रहेगी। कई ट्रेनें निरस्त करने के साथ ही कई के मार्ग में बदलाव किया गया है। आनंद विहार टर्मिनल से रवाना होकर इस रूट से चलने वाली ट्रेनों के मार्ग में भी बदलाव किया गया है। सहरसा-आनंद विहार टर्मिनल (15529/15530), कामख्या-आनंद विहार टर्मिनल(15621/15622) और बापूधाम मोतीहारी-आनंद विहार टर्मिनल (14009/14010) तीन अगस्त तक अपने निर्धारित मार्ग से नहीं चलेगी। इनके मार्ग में बदलाव होने से ट्रेनों के विलंब होने की संभावना है। पिछले कुछ दिनों से वर्षा और संरक्षा कार्य के कारण लंबी दूरी विशेषकर पूर्व दिशा की कई ट्रेनें देरी से अपने गंतव्य पर पहुंच रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि ट्रेनों के सुरक्षित व समय पर चलाने के लिए अलग-अलग स्थानों पर संरक्षा कार्य किया जा रहा है। इस कारण कुछ ट्रेनों की आवाजाही बाधित हो रही है। इस दौरान यात्रियों को कम परेशानी हो इसका ध्यान रखा जा रहा है। संरक्षा कार्य पूरा होने के बाद ट्रेनों के परिचालन में सुधार की उम्मीद है।

दिल्ली सरकार ने सभी कांवड शिविर डिस्पेंसरी से जोडे

परिवहन विशेष।एसडी सेठी। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने जानकारी दी है कि सरकार कांवडियों को उचित सेवा प्रदान कर रही है। इनमें दिल्ली सरकार उनके तमाम कांवड शिविरों को बेहतर हैल्थ सर्विसे देने के लिए डिस्पेंसरियों से कनेक्ट किया है। यहां कैट एंबुलेंस की भी तैनाती रहेगी। मंत्री आतिशी ने दावा किया है कि दिल्ली सरकार ने कांवड यात्रा के दौरान हर तरह से निपटने के लिए जिला प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश दिये है। उन्होने बताया कि सरकार ने तमाम शिविर वाटरप्रूफ बनाए गए है।इनमें कांवडियों के लिए हर जरूरी सुविधा और सुरक्षा के इंतजाम भी किये गए है।

गौर सिटी मॉल के सामने अज्ञात वाहन ने सोते हुए तीन युवकों को कुचला, दो की मौत; एक घायल

ग्रेटर नोएडा में एक अज्ञात वाहन ने फुटपाथ पर सो रहे तीन लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी। जिनमें दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि इस हादसे में एक गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अब घटना के बाद सीसीटीवी के माध्यम से चालक की तलाश खोजबीन कर रही है।

ग्रेटर नोएडा। बिसरख कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बुधवार देर रात एक अज्ञात वाहन ने गौर सिटी मॉल के सामने फुटपाथ पर क्रेड खड़ी करके सो रहे तीन युवकों को कुचल दिया। जिनमें से दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।

पुलिस सीसीटीवी की खंगाल रही फुटेज

सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जबकि एक युवक की हालत गंभीर होने पर उसे नजदीकी यथार्थ अस्पताल भर्ती कराया जहां से उसे दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपित वाहन चालक को तलाश कर रही है।

एक अज्ञात ट्रक ने तीनों को कुचला-पुलिस

पुलिस (Noida Police) के मुताबिक किसान चौक (चार मूर्ति गोलचक्कर) के सर्विस रोड पर औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाली क्रेन खड़ी थी। उसके चालक व परिचालक क्रेन को खड़ी करके सर्विस रोड के समीप ही बुधवार रात करीब साढ़े 11 बजे चारपाई पर सो रहे थे।

तभी गौर सौंदर्यम सोसायटी की तरफ से एक अज्ञात ट्रक आया और उसने तीनों युवकों को कुचल दिया। हादसें में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों की पहचान पूरन व विनोद के रूप में हुई है।

जल्द ही आरोपित की होगी गिरफ्तारी-पुलिस का बयान

जबकि श्याम गंभीर रूप से घायल है। श्याम मूलरूप से गांव नगला मोहन थाना विधुना जिला ओरेया का रहने वाला है। जबकि मृतक पूरन व विनोद ग्राम नानाखेड़ा, जिला बदायूं के रूप में हुई है।

पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपित ट्रक चालक की तलाश कर रही है। बिसरख कोतवाली प्रभारी अरविंद कुमार ने बताया कि ट्रक का नंबर ट्रेस कर लिया गया है। जल्द ही आरोपित पुलिस गिरफ्त में होगा।

कांवड़ यात्रा के बाद साहिबाबाद से चलेंगी गाजियाबाद डिपो की बसें, यात्रियों को चुकाना होगा ज्यादा किराया

परिवहन विशेष न्यूज

गाजियाबाद डिपो की करीब 59 बसें हैं। डिपो से रोजाना करीब नौ से 10 हजार यात्री सफर करते हैं। किराया बढ़ने से इन यात्रियों की जेब पर भार पड़ेगा। साहिबाबाद तक पहुंचने के लिए आटो व रिक्शा को किराया चुकाना पड़ेगा। इससे वह रोडवेज बसों से सफर करने के बजाय वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। इससे रोडवेज बसों में सफर करने वाले यात्रियों में कमी आ सकती है।

साहिबाबाद। कांवड़ यात्रा पूरी होने के बाद गाजियाबाद डिपो की बसों का संचालन साहिबाबाद डिपो से होगा। परिवहन निगम के अधिकारियों ने मुख्यालय से अनुमति ले ली है।

वहीं, यात्रियों को करीब 15 रुपये अधिक किराया चुकाना होगा। गाजियाबाद डिपो का निर्माण 61 करोड़ के बजट से पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड के अंतर्गत हवाई अड्डे की तर्ज पर होना है।

यहां की बसों के संचालन के लिए परिवहन निगम द्वारा बीते माह सिद्धार्थ विहार में नगर निगम की 11500 वर्ग मीटर व साहिबाबाद डिपो पर जगह चिह्नित की थी। साहिबाबाद डिपो से बसों का संचालन करने के लिए अनुमति मिल गई है।

करीब 12 किलोमीटर है दूरी

गाजियाबाद डिपो से इसकी दूरी करीब 12 किलोमीटर है। यहां से बसों का संचालन होने पर हर यात्री पर करीब 15.60 रुपये का अतिरिक्त भार पड़ता। यह भार रोजाना करीब 10 हजार यात्रियों को झेलना पड़ेगा।

साहिबाबाद डिपो से बसों का संचालन करने का हो रहा विरोध

अनुबंधित बस संचालक साहिबाबाद से बसों को चलाने का भी विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि वहां से यात्री नहीं मिलेंगे। यहां की बसों का संचालन मोहननगर से होना चाहिए। यहां से यात्रियों के मिलने की संभावना अधिक रहेगा।

कांवड़ के बाद गाजियाबाद डिपो की बसों का संचालन साहिबाबाद डिपो से किया जाएगा। इसके लिए मुख्यालय से अनुमति ले ली गई है।

-केसरी नंदन चौधरी, क्षेत्रीय प्रबंधक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम।

कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन ने बनाए कंट्रोल रूम

कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण व सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने कंट्रोल रूम बनाए हैं। बुधवार को एडीएम सिटी गंभीर सिंह ने जिले में बनाए गए अलग-अलग कंट्रोल रूम के नंबर जारी किए। राज चौपला मोदीनगर कंट्रोल रूम का नंबर 01232-297750, गंगनहर मुरादनगर कंट्रोल रूम का नंबर 01232-297676, मेरठ रोड तिराहा कंट्रोल रूम का नंबर 0120-2985159, टीला मोड फर्रुखनगर कंट्रोल रूम का नंबर 0120-2985179 व जिला मुख्यालय कंट्रोल रूम का नंबर 0120-2986988 हैं।

कांवड़िए व शिविर संचालक और अन्य श्रद्धालुगण को साफ-सफाई, शौचालय, बिजली, पानी, चिकित्सा आदि कोई समस्या है तो उक्त नम्बर पर अपनी सूचना दर्ज कराते हुए समस्या का समाधान कराया जा सकता है। इसके अलावा पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा भी कंट्रोल रूम नंबर जारी किए गए हें।

सिटी कंट्रोल रूम का नंबर

9643208942, देहात कंट्रोल रूम का नंबर 8929436700, ट्रैफिक कंट्रोल रूम का नंबर 9643322904, ट्रांस हिंडन कंट्रोल रूम का नंबर 9643204440 व मेरठ रोड तिराहा कंट्रोल रूम का नंबर 9643208970 है। इसके अलावा बाढ़ के मद्देनजर एडीएम वित्त एवं राजस्व सौरभ भट्ट ने कंट्रोल रूम के नंबर जारी किए। इसके साथ ही अधिकारियों की अलग-अलग क्षेत्र के लिए जिम्मेदारी तय की है।

पीक ऑवर के 6 घंटे घरों में कैद हो जाती है क्रॉसिंग रिपब्लिक की आबादी, गाजियाबाद सांसद ने जीडीए को लिखा पत्र

क्रॉसिंग रिपब्लिक में दो दर्जन से अधिक सोसायटियों लोग सुबह व शाम पीक ऑवर में छह घंटे जाम से जूझते हैं। यहां पर संकरी सड़क व रेड लाइट का अभाव जाम को बढ़ा रहा है। क्रॉसिंग रिपब्लिक से एबीईएस की ओर जाने वाली सड़क का 100 मीटर टुकड़ा सिर्फ दो लेन का है। क्रॉसिंग रिपब्लिक में ग्लास गेट से प्रवेश करने वाले चौराहे पर रेड लाइट नहीं है।

परिवहन विशेष न्यूज

गाजियाबाद। क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र में बढ़ती जाम की परेशानी को लेकर गाजियाबाद सांसद अतुल गर्ग ने जीडीए (गाजियाबाद विकास प्राधिकरण) को पत्र लिखा है। क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण समेत जाम को खत्म करने के लिए जीडीए को आवश्यक कदम उठाने के लिए निर्देशित किया है।

सांसद ने पत्र में लिखा कि टाउनशिप के अंदर आने व जाने के तीन रास्ते है, तीनों ही बहुत संकरे है। डीपीआर के अनुसार रिछपाल गढ़ी से नोएडा की ओर जाने वाले रास्ते के लिए विकासकर्ता को भूमि खरीद कर या जीडीए के द्वारा भूमि को अधिग्रहित करके उस रास्ते को चौड़ा करना था। इस संबंध में वर्ष 2021 में पत्र लिखा था।

जीडीए बनाएगा रास्ता

पत्र के जवाब में जीडीए ने कहा कि भूमि अर्जन का प्रस्ताव को अग्रसित कर अर्जित करने के प्रस्ताव का सहयोग करेगें। अगर विकासकर्ता इसमें रूचि नहीं ले रहा है तो जीडीए भूमि को अर्जित कर रास्ता बनाएगा।

एनएच-9 शाहबेरी के मुख्य प्रवेश द्वार पर कुछ जमीन का अधिग्रहण कर मुख्य मार्ग से अंदर जाने वाली सड़क को चौड़ा किया जा सकता है। इस संबंध में भूमि स्वामी से लोग मिले। जिसमें भूमि स्वामी ने कहा कि अगर जीडीए जमीन का अधिग्रहण करती है, तो वह जमीन देने को तैयार हैं।

इसी के साथ ही क्षेत्र में फायर स्टेशन बनाने के लिए जीडीए से पत्र के माध्यम से सांसद ने कहा। क्रॉसिंग से एबीईएस की ओर जाने वाले संकरे मार्ग के पास चौड़ा नाला है। चौड़े नाले के ऊपर भी सड़क बनाने से छह लेन रोड आसानी से बन सकती है। सांसद ने पत्र के माध्यम से इसका प्रस्ताव तैयार कर प्रदेश सरकार को देने के लिए जीडीए से कहा है।

सुबह 8 से 11 और शाम 6 से 9 बजे तक लगता है भीषण जाम

क्रॉसिंग रिपब्लिक में सुबह आठ से 11 व शाम छह से नौ बजे तक यहां पर भीषण जाम की स्थिति बनती है। पीक ऑवर के दौरान यहां की सोसायटियों में रहने वाले लोग घरों से निकलने से बचते हैं।

जाम के फंसे वाहन चालकों को निकलने के लिए डेढ़ से दो घंटे तक की मशक्कत करनी पड़ती है। हालत यह है कि यहां पर जाम की स्थिति में सुधार होने के बजाए समस्या काफी बढ़ गई है। शाहबेरी से एबीईएस की ओर जाने वाली रोड पर सुबह व शाम जाम की स्थिति रहती है।

इस जाम में क्रॉसिंग रिपब्लिक इंटीग्रेटेड टाउनशिप में रहने वाले दो दर्जन से अधिक सोसायटी के निवासी परेशान हैं। दस वर्षों से अधिक समय से यहां पर सड़क की 100 मीटर के हिस्से का निर्माण कार्य अधूरा है। सड़क पर जाम लगने से क्रॉसिंग रिपब्लिक सोसायटी में रहने वाले लोगों को टाउनशिप के अंदर प्रवेश व निकास मुश्किल हो जाता है।

ट्रैफिक पर ब्रेक लगाता है 100 मीटर का टुकड़ा

शाहबेरी से एबीईएस तक की दूरी करीब 2.1 किमी है। इस दूरी में एबीईएस से करीब 400 मीटर पहले 100 मीटर का टुकड़ा दो लेन का है। यहां पर एबीईएस व शाहबेरी दोनों ओर से यातायात चार लेन में आता है। दो लेन में यातायात मर्ज होने से चंद मिनटों में लंबा जाम लग जाता है।

यह जाम क्रॉसिंग चौराहे पर पहुंचता है। क्रारसिंग चौराहे पर रेड लाइट नहीं होने से टाउनशिप के अंदर प्रवेश व निकास करतीं गाड़ियों से जाम की स्थिति और विकराल हो जाती है। संकरी रोड के हिस्से का चौड़ीकरण व क्रॉसिंग चौराहे पर रेड लाइट लगाकर काफी हद तक जाम की स्थिति से राहत मिल सकती है।

विजय नगर के पास बनाया गया कट

डीएमई का कट खुलने से बढ़ी यातायात की व्यस्तता डीएमई (दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे) पर प्रवेश व निकास के लिए विजय नगर के पास कट बनाया गया है। इससे पूर्व डीएमई के लिए वाहन चालक इंदिरापुरम से प्रवेश व निकास करते थे।

विजय नगर कट बनने के बाद ग्रेटर नोएडा वेस्ट से डीएमई जाने वाले चालक इस कट से जाने के लिए शाहबेरी व एबीईएस मार्ग का उपयोग करते हैं। डीएमई का नया कट बनने के बाद इस मार्ग पर यातायात की व्यस्तता बढ़ी है। यह भी क्रॉसिंग रिपब्लिक में जाम लगने की एक बड़ी वजह बन रहा है।

जीडीए को करीब 10 वर्ष पहले मास्टर प्लान के मुताबिक सड़क निर्माण का पैसा जमा कर दिया गया है। पता चला है कि जीडीए ने कुछ किसानों को मुआवजा नहीं दिया है इसकी वजह से यह टुकड़ा नहीं बना है। -सुमित अग्रवाल, सीईओ, क्रॉसिंग

कांग्रेस MLA के बेटे की अग्रिम जमानत पर हुई सुनवाई, अब 29 जुलाई को अपनी-अपनी दलील पेश करेंगे दोनों पक्ष

ईडी द्वारा दर्ज किए गए मनी लांड्रिंग मामले में आज कांग्रेस विधायक के बेटे की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई। कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छौक्कर के बेटे विकास छौक्कर ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। इस मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष महला की अदालत में चल रही है। जानिए आखिर पूरा मामला क्या है?

गुरुग्राम। कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छौक्कर Congress MLA Dharm Singh Choudhary के बेटे की अग्रिम जमानत याचिका पर गुरुवार को अदालत में सुनवाई हुई।

इस मामले में अदालत ने 29 जुलाई की तारीख लगा दी है। अग्रिम जमानत को लेकर दोनों पक्षों की जिरह पूरी नहीं हुई है। सोमवार को दोनों पक्ष अपनी-अपनी दलील अदालत में पेश करेंगे।

ईडी ने दर्ज किया था मनी लांड्रिंग का मामला

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2021 में कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छौक्कर व उनके बेटे विकास छौक्कर और सिकंदर छौक्कर पर मनी लांड्रिंग की धाराओं में मामला दर्ज किया।

कंपनी ने फर्जी दस्तावेज से लिया था लाइसेंस

आरोप है कि उन्होंने सेक्टर-68 में माहिरा होम्स के नाम से सोसायटी विकसित करने के लिए निवेशकों के 350 करोड़ रुपये को अपने निजी काम में इस्तेमाल में लिया है। इसके साथ ही उनकी कंपनी ने फर्जी दस्तावेज से लाइसेंस लिया था।

आरोपित विकास की तरफ से दायर की गई याचिका

आरोपित विकास छौक्कर की तरफ से अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई है। शनिवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए गुरुवार के लिए रख दिया था।

प्रतिबंध मुक्त संघ एक नयी किरण का आगाज

ललित गर्ग

आपातकाल में इंदिरा गांधी सरकार की तानाशाही खुलकर सामने दिखी थी, लेकिन उससे पहले भी तानाशाही कदम उठाए जाते रहे थे। दरअसल, 7 नवंबर 1966 को संसद के सामने गोहत्या के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था।

केंद्र की राजग सरकार ने एक महत्वपूर्ण एवं साहसिक आदेश के जरिये सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की गतिविधियों में शामिल होने पर लगी रोक को हटा कर लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक भावना एवं मूल्यों का जीवंत किया है। भले ही इस आदेश को लेकर विपक्षी राजनीतिक दलों की तल्ख प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं संघ ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि तत्कालीन सरकार ने निराधार ही शासकीय कर्मियों के संघ की गतिविधियों में भाग लेने पर रोक लगायी थी। निश्चित ही वर्तमान सरकार का यह निर्णय लोकतांत्रिक व्यवस्था को पुष्ट करने वाला है क्योंकि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एक गैर-राजनीतिक संगठन है, गत 99 वर्षों से सतत राष्ट्र के पुनर्निर्माण एवं समाज की सेवा में संलग्न संघ एक रचनात्मक, सृजनात्मक एवं सांस्कृतिक संगठन है। राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता-अखंडता एवं प्राकृतिक आपदा के समय में संघ के योगदान की विभिन्न राजनीतिक विचारधारा के नेताओं एवं दलों ने प्रशंसा भी की है। इस नये आदेश को लेकर इंडी गठबंधन के दलों में खलबली एवं बौखलाहट का सामने आना स्वाभाविक है, क्योंकि इस आदेश से संघ की ताकत बढ़ेगी, जो इन विपक्षी दलों की चिन्ता का बड़ा कारण है।

दरअसल, आरोप है कि पूर्व की कांग्रेस सरकारों ने समय-समय पर सरकारी कर्मचारियों की संघ के कार्यक्रमों में शामिल होने पर रोक लगा दी थी। संघ की गतिविधियों में शामिल होने पर कर्मचारियों को कड़ी सजा देने तक का प्रावधान लागू किया गया था। सेवानिवृत होने के बाद पेंशन लाभ इत्यादि को ध्यान में रखते हुए भी अनेक सरकारी कर्मचारी चाहते हुए भी संघ की गतिविधियों में शामिल होने से बचते थे। हालांकि, इस बीच मध्यप्रदेश सहित कई राज्य सरकारों ने इस आदेश को निरस्त कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी केंद्र सरकार के स्तर पर यह वैध बना हुआ था। इस मामले में एक वाद इंदौर की अदालत में चल रहा था, जिस पर अदालत ने केंद्र सरकार से सफाई मांगी थी। इसी पर कार्रवाई करते हुए केंद्र सरकार ने नौ जुलाई को एक ऑर्डर जारी करते हुए उक्त प्रतिबंधों को समाप्त करने की घोषणा कर दी। निश्चित ही यह आदेश संघ से जुड़े एवं राष्ट्रीय विचारधारा वाले सरकारी कर्मचारियों के लिये एक नयी किरण है।

आपातकाल में इंदिरा गांधी सरकार की तानाशाही खुलकर सामने दिखी थी, लेकिन उससे पहले भी तानाशाही कदम उठाए जाते रहे थे। दरअसल, 7 नवंबर 1966 को संसद के सामने गोहत्या के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था। 30 नवंबर 1966 को संघ-जनसंघ के प्रभाव से हिलकर इंदिरा गांधी ने सरकारी कर्मचारियों के संघ में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया। क्योंकि संघ व जनसंघ के प्रयासों से लाखों लोग जुटे थे और पुलिस के साथ टकराव में कई लोगों की जान गई थी। गोलीबारी में सैंकड़ों निर्दोष साधु-संत मारे गये थे। इस जघन्य हत्याकांड से क्षुब्ध होकर तत्कालीन गृहमंत्री गुलजारी लाल नंदा ने अपना त्यागपत्र दे दिया था। कांग्रेस पार्टी ने 58 साल पहले वर्ष 1966 में संघ पर लगाये गए प्रतिबंध को हटाने के औचित्य पर सवाल उठाए हैं। कहा जा रहा है कि जनसंघ, वाजपेयी सरकार और मोदी सरकार की पिछली एक दशक की सरकार के दौरान भी यह प्रतिबंध नहीं हटाया गया था, फिर अभी हटाने के पीछे गहरी राजनीतिक चाल है। वहीं संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर का कहना है कि संघ पिछले 99 साल से राष्ट्र के सतत निर्माण व समाज सेवा में संलग्न रहा है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते तत्कालीन सरकार ने शासकीय कर्मचारियों को संघ जैसे रचनात्मक संगठन की गतिविधियों में भाग लेने हेतु निराधार प्रतिबंधित किया था।

क्रांति का फलित है व्यापक स्तर पर होने वाला कोई बड़ा परिवर्तन। व्यक्ति जिस समाज में जीता है, उसकी व्यवस्थाओं, नीतियों और परम्पराओं में जब घुटन का अनुभव करता है जो वह किसी नए मार्ग का अनुसरण करता है। आज आजादी के बाद की राजनीतिक विसंगतियों से पनपी ऐसी ही घुटन से बाहर निकालने के प्रयत्न वर्तमान सरकार द्वारा हो रहे हैं। ऐसा ही एक विशिष्ट उपक्रम है सरकारी कर्मचारियों के संघ की गतिविधियों में भाग लेने पर लगा प्रतिबंध का हटना। इसको लेकर भी विपक्षी दलों द्वारा जनता को गुमराह किया जा रहा है, राष्ट्र की एकता को विखंडित करने के प्रयास हो रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने संघ की गतिविधियों में कर्मचारियों के शामिल होने पर लगे प्रतिबंध को हटाकर नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा की है। निःसंदेह, सरकार का यह निर्णय लोकतंत्र और संविधान की भावना को मजबूत करनेवाला है। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार देता है कि वह विविध सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक संगठनों में शामिल हो सके। एक सामान्य नागरिक की भांति यह अधिकार कर्मचारियों को भी प्राप्त है कि अपने कार्यालयीन समय के बाद सामाजिक गतिविधियों का हिस्सा हो सकते हैं। परंतु, लोकतंत्र और संविधान की दुहाई देनेवाली कांग्रेस की सरकार ने तानाशाहीपूर्ण तरीके से संघ की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था, जो एक प्रकार से राष्ट्रीय विचार के प्रति झुकाव रखनेवाले लोगों को हतोत्साहित करने का प्रयास ही था। कांग्रेस की नीयत को समझिए कि उसने ऐसा कोई प्रतिबंध इस्लामिक, ईसाई, कम्युनिस्ट और अन्य प्रकार के संगठनों की गतिविधियों में शामिल होने पर नहीं लगाया था। यानी कर्मचारी इस्लामिक एवं ईसाई संगठनों से जुड़ सकता था लेकिन हिन्दू संगठन की गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकता था। कांग्रेस की इस तानाशाही एवं द्वेष का उत्तर संघ ने तो कभी नहीं दिया लेकिन समाज ने अवश्य ही कांग्रेस को आईना दिखाने का कार्य किया।

कांग्रेस लगातार आठ दशकों में हिन्दू-संस्कृति को कमजोर करने की राजनीतिक चालें चलती रही है। जबकि हिन्दू धर्म नहीं, विचार है, संस्कृति है। हिन्दू राष्ट्र होने का अर्थ धर्म से न होकर हिन्दू संस्कृति के सर्वग्राही भाव से है। हिन्दू संस्कृति उदारता का अन्तर्निहित शंखनाद है क्योंकि पूरे विश्व में यह अकेली संस्कृति है जो बहुविचारवाद यानी सभी धर्म, विचार एवं संस्कृतियों को स्वयं में समेटे हैं। हमारे ऋषियों ने हमें यह उपदेश दिया कि 'सत्यं बूर्यात न बूर्यात सत्यं अप्रियं' अर्थात सच बोलो मगर कड़वा सच मत बोलो। हिन्दू संस्कृति की यही महानता और विशेषता रही है कि प्रिय सत्य की वकालत तो करती है मगर इसके कटु होने पर निषेध करने को भी कहती है। यह हिन्दू संस्कृति अहिंसा की संस्कृति है पर जरूरत पड़ने पर शस्त्र उठाकर स्व-रक्षा की बात भी कहती है। हिन्दू शब्द से ही स्वराष्ट्र का बोध होता है जो कि हिन्दू संस्कृति के वृहद स्वरूप का ही सौपान है। लेकिन राजनीतिक कारणों से कांग्रेस एवं अन्य ताकतों ने हिन्दू संस्कृति को निस्तेज करने, संघ को दबाने एवं समाप्त करने के लिए अनेक प्रयत्न किए। इस आदेश के अतिरिक्त तीन बार संघ पर पूर्ण प्रतिबंध भी लगाया। संघ की छवि खराब करने के लिए बड़े-बड़े नेताओं की ओर से मिथ्या प्रचार भी किया गया। अपने समर्थक बुद्धिजीवियों से पुस्तकें भी लिखवायी गईं। लेकिन निस्वार्थ भाव से देश और समाज के लिए कार्य करनेवाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कोई रोक नहीं सका।

अपनी 99 वर्ष की यात्रा में संघ ने लगातार प्रगति एवं विस्तार ही किया है। अपने विचार, आचरण एवं सेवाकार्यों से संघ ने समाज का विश्वास जीता, जिसके कारण समाज सदैव संघ के साथ खड़ा रहा। कांग्रेस सरकार का तात्कालिक आदेश भी सरकारी कर्मचारियों को संघ कार्य में सहभागी होने से रोक नहीं सका। कई ऐसे उहाहरण हैं, जिनमें संघ गतिविधि में शामिल होने पर कांग्रेस की सरकारों ने सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की। लेकिन वे सभी मामले न्यायालय में टिक नहीं सके। संघ के स्वयंसेवक न्यायालय से जीतकर आए। उनकी छोटी-छोटी जीतों की श्रृंखला ने भी यह साबित किया कि संघ की गतिविधियों में शामिल होने से रोकने के लिए लगाया गया कांग्रेस सरकार का आदेश निरर्थक और संविधान एवं मौलिक अधिकारों की मूल भावना के विरुद्ध था।

– :सौजन्य :–
ईवी ड्राइव द फ्यूचर
EV Drive the Future

हरियाणा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाने के लिए सम्मेलन का किया आयोजन

परिवहन विशेष न्यूज

हरियाणा सरकार ने बुधवार, 24 जुलाई को गैर-लाभकारी सार्वजनिक नीति थिंक टैंक, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाने के लिए एक हितधारक सम्मेलन का आयोजन किया।

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पंचकूला के अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) सचिन गुप्ता ने कहा कि सम्मेलन ने बेहतर नीति दृष्टिकोण अपनाने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के बीच बातचीत के द्वार खोल दिए हैं, जिससे हरियाणा की विद्युतीकरण यात्रा में तेजी आएगी।

बयान में कहा गया है कि हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जो हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर जैसे गैर-सड़क ईवी के लिए प्रोत्साहन दे रहा है और जीवाश्म ईंधन वाले सरकारी वाहनों, सार्वजनिक बसों, वाणिज्यिक बेड़े और लॉजिस्टिक्स वाहनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का लक्ष्य रखता है। राज्य ने 2029 तक गुरुग्राम और फरीदाबाद में सार्वजनिक परिवहन वाहनों के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य भी रखा है।

इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन के प्रबंध निदेशक (भारत) अमित भट्ट ने कहा कि हरियाणा की ईवी नीति मांग प्रोत्साहन के लिए ट्रैक्टरों को शामिल करने वाली पहली नीति थी। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम और फरीदाबाद ऐसे प्रकाश स्तंभ शहर हो सकते हैं जो राज्य के बाकी हिस्सों के विद्युतीकरण को बढ़ावा दे सकते हैं।रही है।

ईवी निर्माता विनफास्ट का भारत में मेगा स्मार्ट सिटी बनाने का सपना, हैदराबाद में कर रही करोड़ों का निवेश

परिवहन विशेष न्यूज

वियतनाम की इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी विनफास्ट ने भारत में भारी निवेश करने की योजना बनाई है। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार कंपनी ने हैदराबाद में 1000 एकड़ जमीन पर मेगा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट स्थापित करने की योजना बनाई है।

इससे पहले कंपनी ने तमिलनाडु में 4000 करोड़ रुपये का निवेश कर इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण सुविधा स्थापित की थी। अब कंपनी ने हैदराबाद में अपने नए प्रोजेक्ट के लिए जमीन की तलाश शुरू कर दी है।

इस संबंध में विनफास्ट इंडिया के सीईओ फाम सान्ह चाऊ के नेतृत्व में एक दल ने तेलंगाना के आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, संचार, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री डी. श्रीधर बाबू से मुलाकात की। सूत्रों ने बताया कि "चर्चा बड़े पैमाने की सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, स्थायी स्मार्ट शहरी गतिशीलता समाधानों, भविष्य के शहरों के लिए सेवाओं और सामाजिक आवास पहलों पर केंद्रित थी."

विनफास्ट ने हाल ही में तमिलनाडु में इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए 4,000 करोड़ रुपये (लगभग 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर) का निवेश किया है।

रिपोर्ट के अनुसार चर्चा से परिचित लोगों ने बताया कि मंत्री ने कहा कि बढ़ते शहरी प्रवास के कारण हैदराबाद में अगले 15 वर्षों में तेलंगाना की आधी आबादी रहने वाली है, जिससे मौजूदा बुनियादी ढांचे पर बहुत दबाव पड़ेगा। उन्होंने शहर की बढ़ती आबादी के लिए बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए इन महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर सहयोग करने के लिए विश्वसनीय भागीदारों को खोजने के महत्व पर जोर दिया।

उम्मीद है कि विनफास्ट 2025 के त्योहारी सीजन तक अपनी पहली स्थानीय रूप से असेंबल की गई कार लॉन्च करेगी। वाहन की कीमत 25-30 लाख रुपये के बीच होने की उम्मीद है, जो इसे भारत के विस्तारित ईवी बाजार के प्रीमियम किफायती सेगमेंट में रखेगी, जिसकी अनुमानित रेंज 300-500 किमी है।

विनफास्ट 17 से 22 जनवरी, 2025 को होने वाले भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में अपनी भविष्य की योजनाओं का आधिकारिक तौर पर खुलासा करेगी।

आईआईटी दिल्ली ने हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन डिजाइन में सर्टिफिकेट प्रोग्राम किया शुरू

परिवहन विशेष न्यूज

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों के डिजाइन पर केंद्रित एक नया सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू किया है, ताकि वाहन विद्युतीकरण में विशेषज्ञता की बढ़ती जरूरत को पूरा किया जा सके, क्योंकि ऑटोमोटिव क्षेत्र स्थिरता की ओर बढ़ रहा है।

आईआईटी दिल्ली की आधिकारिक घोषणा के अनुसार यह छह महीने का सर्टिफिकेट प्रोग्राम मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोटिव और संबंधित क्षेत्रों के इंजीनियरों के लिए बनाया गया है, जो ईवी/एचईवी प्रौद्योगिकियों में एक मजबूत आधार बनाना चाहते हैं। यह ईवी/एचईवी डोमेन में अपने मौजूदा ज्ञान को बढ़ाने के इच्छुक पेशेवरों का भी समर्थन करता है।

इस कार्यक्रम में थर्मोडायनामिक्स, आंतरिक दहन इंजन, इलेक्ट्रिक मशीन और ड्राइव, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव हाइब्रिडाइजेशन और बैटरी डिजाइन और मॉडलिंग जैसे आवश्यक विषयों को शामिल किया गया है। इस व्यापक पाठ्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को क्षेत्र में नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करना है।

प्रमाणपत्र कार्यक्रम प्रतिभागियों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करेगा:

आंतरिक दहन इंजन की परिचालन विशेषताओं का वर्णन

वाहन संकरण और विद्युतीकरण में शामिल प्रक्रियाओं का विवरण

HEV में प्रयुक्त विभिन्न विद्युत मशीनों और प्रणोदन प्रौद्योगिकियों की व्याख्या

विभिन्न ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के पीछे के सिद्धांतों को रेखांकित

बैटरी के प्रदर्शन, विश्वसनीयता और सुरक्षा के परीक्षण और मॉडलिंग के तरीकों पर चर्चा

इस कार्यक्रम के लिए पात्रता में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों (UGC/AICTE/DEC/AIU/ राज्य सरकार/मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय संस्थानों) से इंजीनियरिंग स्नातक (मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोटिव और संबंधित क्षेत्र) या डिप्लोमा धारक (10+2+3) शामिल हैं। कक्षाएं 13 अक्टूबर, 2024 से शुरू होंगी। कार्यक्रम की फीस 1,10,000 रुपये प्लस जीएसटी है।

घोषणा के अनुसार जो छात्र न्यूनतम 50% ग्रेड और कम से कम 50% उपस्थिति दर के साथ कार्यक्रम पूरा करेंगे, उन्हें आईआईटी दिल्ली में सतत शिक्षा कार्यक्रम (सीईपी) से पाठ्यक्रम पूरा होने का प्रमाण पत्र मिलेगा।

ऑटो-लेक इलेक्ट्रिक की मिड ड्राइव मोटर और कंट्रोलर

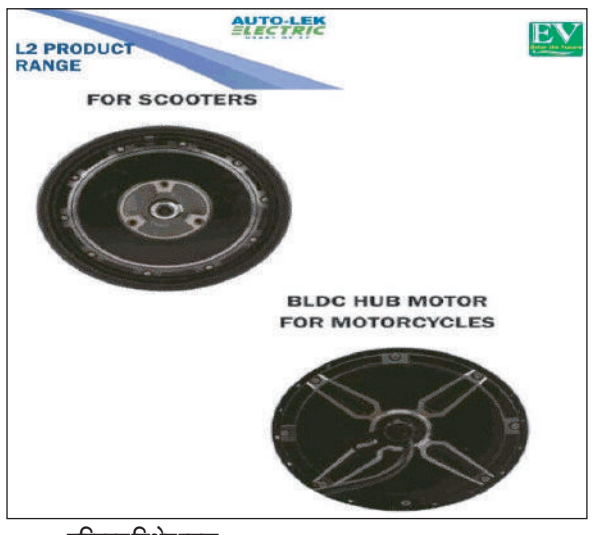

परिवहन विशेष न्यूज

ऑटो-लेक इलेक्ट्रिक द्वारा ट्रैक्शन मोटर्स और हब मोटर्स को विशेष रूप से भारतीय ड्राइविंग परिस्थितियों के लिए विकसित किया गया है, जिसमें ओवरलोडिंग कारक और सड़क की स्थिति को ध्यान में रखा गया है।

मोटर के प्रदर्शन के साथ-साथ इसकी स्थायित्व और सीलिंग क्षमता को भी सत्यापित करने के लिए विस्तृत सत्यापन परीक्षण किए गए। ऑटो-लेक इलेक्ट्रिक की बीएलडीसी हब मोटर स्कूटर और मोटरसाइकिल के लिए उच्च शक्ति घनत्व के संबंध में पूरी तरह से संगत और अनुकूलित हैं। विद्युत प्रणाली का कॉम्पैक्ट डिज़ाइन इसकी खूबियों में से एक है। यह प्रणाली सभी ड्राइविंग स्थितियों में उच्च प्रदर्शन प्रदान करती है।

ऑटो-लेक इलेक्ट्रिक हर उपभोक्ता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए दो पहिया वाहनों के लिए उन्नत हाई-टेक बीएलडीसी/पीएमएसएम मोटर और कंट्रोलर के साथ ईवी के भविष्य को आकार देता है।

सर्वोटेक पावर को बीपीसीएल और अन्य ओईएम से डीसी फास्ट ईवी चार्जर्स की लगभग 400 इकाइयों का मिला अतिरिक्त ऑर्डर मिला

परिवहन विशेष न्यूज

ईवी चार्जर्स और सौर समाधान की अग्रणी प्रदाता कंपनी सर्वोटेक पावर सिस्टम्स लिमिटेड ने हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य ईवी चार्जर ओईएम से लगभग 400 डीसी फास्ट ईवी चार्जर्स के लिए अतिरिक्त ऑर्डर प्राप्त किया है।

कंपनी की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार लगभग 20 करोड़ रुपये की लागत वाली बीपीसीएल ई-ड्राइव परियोजना में देश भर में, मुख्य रूप से ईंधन स्टेशनों पर चार्जरों का विनिर्माण, वितरण, स्थापना और तैनाती शामिल होगी।

इससे पहले कंपनी को बीपीसीएल और अन्य ईवी चार्जर ओईएम द्वारा 1800 डीसी फास्ट ईवी चार्जर्स के लिए 120 करोड़ का ऑर्डर मिला था, अब इस ऑर्डर में 20% की वृद्धि की गई है।

सर्वोटेक पावर सिस्टम्स लिमिटेड की निदेशक सारिका भाटिया ने कहा, ₹सर्वोटेक बीपीसीएल के लिए काम करके बेहद उत्साहित है और बीपीसीएल ने हम पर जो भरोसा जताया है, उस पर खरा उतरने के लिए प्रतिबद्ध है। समय-समय पर हमने अपनी उत्पादन टीम के साथ अपनी विनिर्माण क्षमताओं का प्रदर्शन किया है, जो इन-हाउस बेहतरीन उत्पादों को वितरित करने पर लगातार ध्यान केंद्रित करते हुए काम कर रही है। हम उद्योग में नए मानक स्थापित करते हुए सेवा और परिचालन दक्षता के उच्चतम मानकों को बनाए रखना जारी रखेंगे।

उन्होंने कहा, ₹हमारे पर्यावरण के प्रति जागरूक और बेहतर ईवी चार्जर भारत भर में टिकाऊ ईवी चार्जिंग समाधानों की बढ़ती मांग को पूरा कर रहे हैं, जिससे ईवी उपयोगकर्ताओं के व्यापक जनसांख्यिकीय समूह के लिए ईवी चार्जिंग सुविधाओं की पहुंच, सामर्थ्य और उपलब्धता बढ़ रही है।"

हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड और केरल स्टार्टअप मिशन ने समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर

परिवहन विशेष न्यूज

हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड और केरल स्टार्टअप मिशन ने केरल में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। डॉ. रतन यू केलकर, आईएएस, सचिव (ईएंडआईटीडी) की उपस्थिति में हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड के मुख्य व्यवसाय अधिकारी, इमर्जिंग मोबिलिटी, श्री स्वदेश कुमार श्रीवास्तव और केएसयूएम के सीईओ श्री अनूप पी अंबिका द्वारा हस्ताक्षरित यह साझेदारी राज्य में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इससे स्टार्टअप को मोबिलिटी, बैटरी तकनीक, ईवी आदि के क्षेत्रों में हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड के साथ मिलकर काम करने के अवसर मिलेंगे। इस साझेदारी का उद्देश्य स्टार्टअप को एचएमसीएल के फोकस क्षेत्रों से जोड़ना, संसाधन और सहायता प्रदान करना और जागरूकता अभियान चलाना है।

बीवाईडी ने 1,50,000 वाहनों की वार्षिक क्षमता वाले थाईलैंड संयंत्र के उद्घाटन का मनाया जश्न

परिवहन विशेष न्यूज

बीवाईडी ने थाईलैंड के रेयॉन्ग में अपने थाईलैंड संयंत्र के उद्घाटन और 8 मिलियनवें नए ऊर्जा वाहन के उत्पादन का जश्न मनाया। इस संयंत्र की वार्षिक क्षमता 1,50,000 वाहनों की है और इससे 10,000 नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है।

बीवाईडी ने थाईलैंड में अपने संयंत्र का उद्घाटन किया, जो कंपनी के नवीन ऊर्जा वाहन उद्योग के वैश्विक विस्तार में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।

थाईलैंड संयंत्र मात्र 16 महीनों में बनकर तैयार हो गया है, जिसकी वार्षिक क्षमता 150,000 वाहनों की है तथा इससे 10,000 नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है, जो थाईलैंड तथा समूचे आसियान में नवीन ऊर्जा वाहन उद्योग के विकास को आगे बढ़ाने के लिए बीवाईडी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

88 देशों और क्षेत्रों में मजबूत वैश्विक उपस्थिति के साथ बीवाईडी का लक्ष्य दुनिया भर के उपभोक्ताओं की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी और नवीन उत्पादों का लाभ उठाते हुए अपनी बाजार उपस्थिति और उत्पादन क्षमता का विस्तार जारी रखना है।

कंपनी ने 8 मिलियनवें नए ऊर्जा वाहन के रूप में डॉल्फिन मॉडल का अनावरण किया। थाईलैंड में बीवाईडी के निवेश की प्रशंसा थाईलैंड और पूरे आसियान में नए ऊर्जा वाहन उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए की जाती है।

कंपनी ने वैश्विक निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है और थाईलैंड में अधिक शुद्ध इलेक्ट्रिक और प्लग-इन हाइब्रिड मॉडल लॉन्च करने का लक्ष्य रखती है। बीवाईडी 88 देशों और क्षेत्रों में उपस्थिति के साथ नई ऊर्जा वाहनों का एक अग्रणी वैश्विक प्रदाता है। अभिनव प्रौद्योगिकी और वैश्विक विस्तार पर ध्यान केंद्रित करने के साथ बीवाईडी का लक्ष्य वैश्विक नई ऊर्जा वाहन बाजार में एक नेता के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करना है।

नई ऊर्जा वाहनों में वैश्विक अग्रणी बीवाईडी ने विदेशों में अपनी उपस्थिति में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है। 2023 में इसने निर्यात में 337% की साल-दर-साल वृद्धि हासिल की, जो 2,43,000 वाहनों तक पहुँच गई। इस वर्ष की पहली छमाही में बीवाईडी ने वैश्विक स्तर पर 1.607 मिलियन नई ऊर्जा वाहन बेचे, जो साल-दर-साल 28% की वृद्धि है। इनमें से 2,03,000 से अधिक निर्यात किए गए, जो साल-दर-साल 173.8% की वृद्धि दर्शाता है। वर्तमान में बीवाईडी के नए ऊर्जा वाहन दुनिया भर के 88 देशों और क्षेत्रों में मौजूद हैं, जिनमें थाईलैंड, ब्राजील, हंगरी और उज्बेकिस्तान में यात्री कार उत्पादन केंद्र स्थापित हैं।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जीवन के सभी पहलुओं पर राज कर रहा है

विजय गर्ग

उन्नत एआई-संचालित प्लेटफार्मों में शैक्षिक परिदृश्य को बदलने और व्यक्तिगत शिक्षा की दिशा में सही कदम उठाने की क्षमता है जहां छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार समाधान तैयार किए जा सकते हैं। और नवाचार हमेशा ऐसे सभी समाधानों के मूल में रहेगा।

भारत में शिक्षा प्रणाली में पिछले एक दशक में काफी बदलाव आया है। बदलते समय के साथ तालमेल बिठाने के लिए, शिक्षकों ने अपनी शिक्षण पद्धतियां विकसित कीं, जबकि विशेषज्ञों ने उभरती जरूरतों के आधार पर पाठ्यक्रम तैयार किया। डिजिटलीकरण ने शिक्षा में एक नया दृष्टिकोण भी लाया है, विशेषकर शिक्षाशास्त्र के संदर्भ में। भले ही छात्रों ने वीडियो की मदद से अवधारणाओं को सीखने का आनंद लिया, उन्हें नए विचारों और अवधारणाओं में बेहतर अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई जो उनके तत्काल वातावरण में पहुंच योग्य नहीं थे। फिलहाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जीवन के सभी पहलुओं पर राज कर रहा है। के-12 शिक्षा छात्रों के साथ-साथ शिक्षकों को लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न एआई-आधारित अनुप्रयोगों को अपना रही है। उदाहरण के लिए, एआई-आधारित विश्लेषण की मदद से, शिक्षक ज्ञान अंतराल की पहचान कर सकते हैं और छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार अपनी शिक्षाओं को अनुकूलित कर सकते हैं। हालाँकि, यह सिर्फ हिमशैल का सिरा है। एआई स्वचालित ग्रेडिंग, शिक्षकों के लिए समय बचाने और उन्हें बेहतर शिक्षण पद्धतियों पर विचार-मंथन करने के लिए अधिक समय देने में भी मदद कर सकता है। उन्नत एआई-संचालित प्लेटफार्मों में शैक्षिक परिदृश्य को बदलने और व्यक्तिगत शिक्षा की दिशा में सही कदम उठाने की क्षमता है जहां छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार समाधान तैयार किए जा सकते हैं। और नवाचार हमेशा ऐसे सभी समाधानों के मूल में रहेगा। जेनेसिस ग्लोबल स्कूल के निदेशक इस बारे में एक व्यापक मार्गदर्शिका साझा करेंगे कि एआई भारत में के-12 छात्रों के लिए शिक्षा को कैसे तैयार कर रहा हैः शिक्षा में एआई का प्रभाव विज्ञापन शिक्षा में एआई के सबसे गहरे प्रभावों में से एक छात्रों के बीच रुझान, पैटर्न और सीखने की शैलियों को समझने के लिए विशाल मात्रा में डेटा का विश्लेषण करने की क्षमता है। यह अमूल्य अंतर्दृष्टि न केवल निर्देशात्मक प्रथाओं को सूचित करती है बल्कि विभिन्न शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप सीखने के अनुभवों को बेहतर ढंग से अनुकूलित करने में भी सक्षम बनाती है। एआई-संचालित स्वचालित ग्रेडिंग सिस्टम मूल्यांकन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने का एक शानदार तरीका है। वे समय और प्रयास बचाते हैं जो शिक्षक मैन्युअल सुधार पर बर्बाद करते हैं। एआई का यह समय बचाने वाला पहलू शिक्षकों को सार्थक छात्र बातचीत और व्यक्तिगत समर्थन के लिए अधिक संसाधन आवंटित करने की अनुमति देता है, जिससे अंततः सीखने का अनुभव समृद्ध होता है। एआई शैक्षिक वातावरण में निर्बाध संचार प्रणाली की सुविधा प्रदान करता है, जिससे सूचना और फीडबैक चैनलों का कुशल प्रसार संभव हो पाता है। इसके अतिरिक्त, व्यक्तिगत छात्र की जरूरतों के अनुरूप ट्यूटोरियल प्रदान करके, एआई प्लेटफॉर्म जटिल अवधारणाओं को समझने में अतिरिक्त सहायता प्रदान करते हैं, जिससे गहरी समझ और जुड़ाव को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा, एआई की डेटा विश्लेषण क्षमताएं शैक्षिक नेताओं को छात्र प्रदर्शन मेट्रिक्स में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं, जिससे सीखने के परिणामों में सुधार लाने के उद्देश्य से लक्षित हस्तक्षेप की सुविधा मिलती है। ताकत और कमजोरी के क्षेत्रों की पहचान करके, शिक्षक प्रत्येक छात्र के लिए सीखने के अनुभवों को अनुकूलित करने के लिए रणनीतियों को लागू कर सकते हैं। कक्षा से परे, एआई एक वैश्विक कनेक्टिविटी को बढ़ावा देता है जो भौगोलिक सीमाओं को पार करता है, वैश्विक स्तर पर सहयोग और ज्ञान साझा करने की सुविधा प्रदान करता है। यह अंतर्संबंध शिक्षार्थियों को विविध दृष्टिकोण और अनुभवों के साथ सशक्त बनाता है, उनकी शैक्षिक यात्रा को समृद्ध करता है और उन्हें आत्मविश्वास और क्षमता के साथ तकनीकी रूप से उन्नत दुनिया में नेविगेट करने के लिए तैयार करता है। शिक्षा में एआई का एकीकरण विज्ञापन संक्षेप में, शिक्षा में एआई का एकीकरण व्यक्तिगत, कुशल और की दिशा में एक परिवर्तनकारी बदलाव का प्रतिनिधित्व करता हैनवीन शिक्षण अनुभव. इन एआई-आधारित प्लेटफार्मों का उपयोग करने से शिक्षकों को एक क्लिक में सारी जानकारी उपलब्ध होने में मदद मिलेगी, यह उल्लेखनीय रूप से उनके बोझ को कम करेगा, खासकर जब सांसारिक कार्यों की बात आती है। एआई शिक्षकों को सीखने के पैटर्न की पहचान करने में भी मदद करेगा, इस प्रकार उन्हें उन विषयों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम करेगा जहां छात्र सामान्य रूप से संघर्ष करते हैं और उन्हें उन क्षेत्रों में प्रोत्साहित करेंगे जहां वे अच्छा कर रहे हैं। भले ही समय के साथ एआई संभवतः अधिक नवीन समाधान लाएगा, शिक्षा समुदाय इन परिवर्तनों को अपनाने के लिए हमेशा तैयार रहेगा, क्योंकि उनके मूल में अपने छात्रों का कल्याण है।

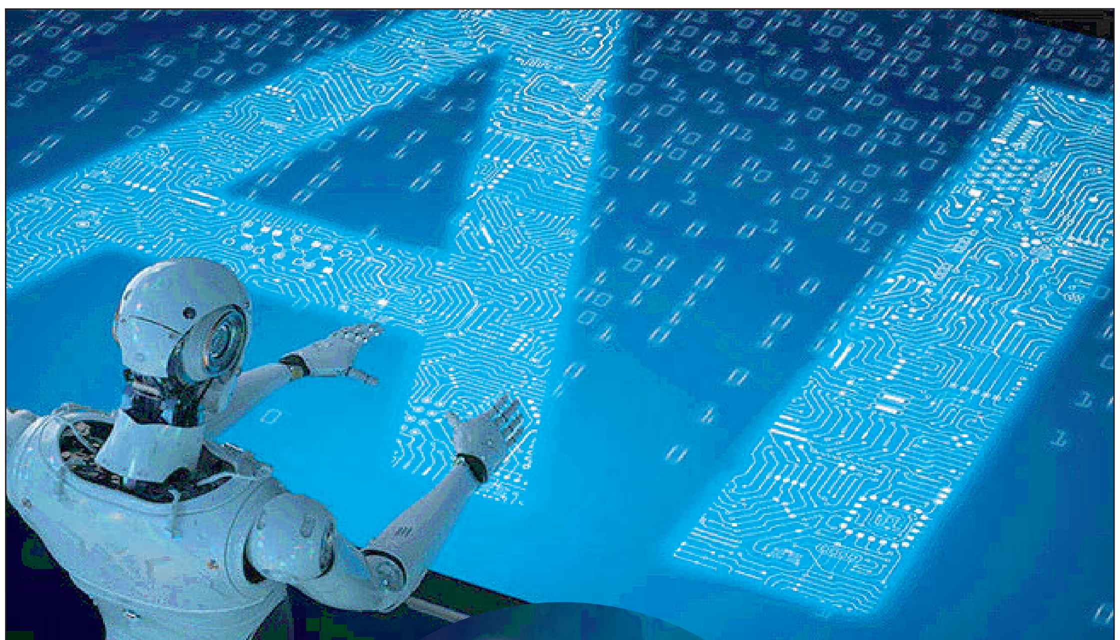

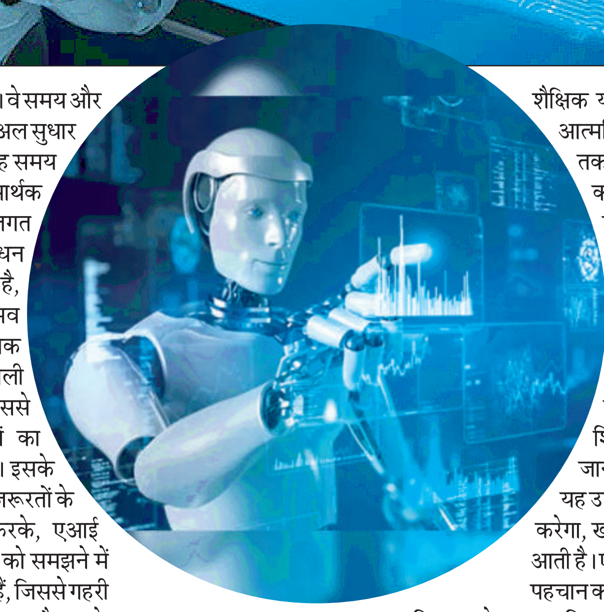

संपादक की कलम से

बेरोजगारी की इंटर्नशिप

बजट का सबसे महत्वपूर्ण और आकर्षक प्रस्ताव है-युवाओं की इंटर्नशिप। यह एक व्यापक वोट बैंक भी साबित हो सकता है। यह ऐसा प्रशिक्षण भी साबित हो सकता है, जिससे बेरोजगारी कम होने लगे, लिहाजा रोजगार बढ़ता जाए। इस परियोजना के तहत भारत सरकार 500 बड़ी कंपनियों को छांटेगी। पांच साल के दौरान 4.10 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वायदा किया गया है। कंपनियां हर साल 20 लाख युवाओं का कौशल विकसित करेंगी। इस तरह 5 साल के दौरान कुल एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के जरिए हुनरमंद किया जाएगा। इंटर्नशिप के दौरान कंपनियां 5000 रुपए प्रति माह का भत्ता देंगी और एकमुश्त 6000 रुपए भी देंगी। बजट में इस कार्यक्रम के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का आवंटन रखा गया है। बेरोजगारी से लडने और निरंतर रोजगार-सृजन की यह महत्वपूर्ण परियोजना बताई जा रही है। बेरोजगारी सबसे अहम समस्या और चुनौती है, यह आम चुनाव के जनादेश से स्पष्ट हो चुका है। भाजपा को इस बार अकेले ही स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं हुआ है। केंद्र में गठबंधन सरकार जारी है। बहरहाल इंटर्नशिप की पात्रता आयु 21-24 साल है। कई और शर्तें लगाई गई हैं, जो व्यावहारिक नहीं हैं। उनके कारण बेरोजगारी उन्मूलन का लक्ष्य अधूरा ही रह सकता है। पहला यथार्थ तब सामने आएगा, जब 500 कंपनियों के नाम सार्वजनिक किए जाएंगे। वे कंपनियां किन क्षेत्रों में परचम लहरा रही हैं और अच्छी तरह स्थापित हैं, यह खुलासा भी देश के सामने आना चाहिए। इंटर्नशिप के लिए युवाओं का चयन किस तरह होता है, यह भी गौरतलब होगा। इंटर्नशिप का पहला चरण दो साल का है। यह भी सवाल है कि क्या युवाओं की निरंतरता बनी रहेगी? दूसरा यथार्थ तब सामने आएगा, जब युवा किसी रोजगार का अनुभव तो हासिल कर लेंगे, लेकिन क्या वही कंपनियां उन्हें नौकरी देंगी? सरकार के सामने यह गंभीर चुनौती रही है कि श्रम-गहन क्षेत्रों में निजी निवेश बढ़ नहीं पा रहा है। दरअसल कंपनियों की ऐसे क्षेत्रों में निवेश की दिलचस्पी ही कम है, लिहाजा नए श्रम की भीड़ बढ़ाने के मद्देनजर कंपनियां नए, हुनरमंद युवाओं को नौकरी क्यों देंगी? कुछ अपवाद हो सकते हैं। बजट में दावा किया गया है कि 2 करोड़ को पहली नौकरी पर सरकार सीधी मदद देगी और युवा के आनंद को साझा करेगी। इस योजना से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को जोड़ा गया है। बजट का फोकस गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी यानी 'ज्ञान' पर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आम चुनाव के दौरान इन चार वर्गों को ही चिह्नित किया था। उन्हें ही अपनी चार जातियां बताया था। बजट में युवाओं के रोजगार के लिए सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को 100 करोड़ रुपए तक का कर्ज देने की गारंटी सरकार ने दी है। एमएसएमई में अभी 11.10 करोड़ लोग जुड़े हैं। सरकार ने 2025 तक इनमें 5 करोड़ रोजगार जोडने का लक्ष्य रखा है। सवाल फिर दोहरा रहे हैं कि ये रोजगार कारोबारी होंगे अथवा नौकरी के रूप में दिए जाएंगे! इनके अलावा, आधारभूत ढांचे पर बजट में 11.11 लाख करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव है। सरकार का लक्ष्य है कि विभिन्न निर्माण-कार्य होंगे, तो रोजगार का विस्तार भी होगा। ऐसे इंटर्नशिप कार्यक्रम अमरीका, ब्रिटेन, कनाडा सरीखे विकसित देशों में भी चलाए जा रहे हैं। दरअसल सरकार कोई भी हो, कल्याणकारी परियोजनाओं और सबसिडी मुहैया करा कर भी रोजगार नहीं दे सकती। बेरोजगारी की चुनौती से नहीं लड़ सकती। सरकार को एहसास हो रहा है कि बेरोजगारी को संबोधित करने के लिए उसके पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं, लिहाजा इस अभियान में निजी क्षेत्र को जोड़ा जा रहा है। सरकार के आग्रह पर रोजगार और नौकरियां निजी क्षेत्र पैदा करेंगे। बदले में सरकार नियोक्ताओं को सबसिडी देगी। प्रधानमंत्री मोदी की 9 प्राथमिकताएं बजट के लिए तय की गई हैं। मसलन-मैन्यूफैक्चरिंग, सेवा क्षेत्र, रोजगार, कौशल विकास, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, आधारभूत ढांचा, सामाजिक न्याय आदि।

राय

भारतीय शिक्षा प्रणालीः एक जीवंत राष्ट्र का निर्माण

(भारत एक मजबूत, अधिक जीवंत राष्ट्र बनाने के सही रास्ते पर है जहां प्रतिभा, ज्ञान और कौशल पनपते हैं।)

विजय गर्ग

आधुनिक प्रथाओं के साथ ज्ञान और कौशल विकास को एकीकृत करके, हम ऐसे युवाओं का पोषण कर सकते हैं जो कुशल और भावनात्मक और शारीरिक रूप से लचीले हों। भारत की शैक्षिक नीतियां एक संतुलित दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए तैयार हैं जो आधुनिक कौशल के साथ सीखने को एकीकृत करती है, अनावश्यक बोझ को कम करती है और प्रत्येक बच्चे की अद्वितीय क्षमता का पोषण करती है। तेजी से विकसित हो रही दुनिया में नए अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम भविष्य के लिए तैयार युवाओं के निर्माण के लिए ये प्रयास महत्वपूर्ण हैं। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी शैक्षिक सुधारों और कौशल विकास के मुखर समर्थक रहे हैं। सरकार द्वारा उठाए गए ऐतिहासिक कदमों में से एक लगभग चार दशकों के बाद स्थापित नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) २०२० की शुरुआत है। नई शिक्षा नीति (एनईपी) २०२० की शुरुआत ने सकारात्मक लाभांश देना शुरू कर दिया है। एक परिवर्तनकारी नीति होने के नाते, यह कौशल प्रशिक्षण को छठी कक्षा से शिक्षा प्रणाली में एकीकृत करके औपचारिक रूप देती है। यह नीति स्कूली शिक्षा को कौशल के साथ जोड़ने के महत्व को रेखांकित करती है, और अब तीसरी कक्षा से आगे की कक्षाओं के लिए शिक्षण-अधिगम सामग्री भी उपलब्ध कराई जा रही है। सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और व्यावहारिक क्षेत्रों को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की सरकार की योजना विविध और प्रतिभाशाली युवा शक्ति की कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में एक आशाजनक कदम है। इसके अतिरिक्त, स्कूल बैग नीति का उद्देश्य स्कूल बैग के भौतिक बोझ को संबोधित करके छात्रों की भलाई को बढ़ाना है। यह नीति शैक्षिक सामग्रियों को सुव्यवस्थित करने, डिजिटल संसाधनों को बढ़ावा देने और एर्गोनोमिक डिज़ाइन को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है। असम और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने शैक्षणिक सत्र २०२४-२५ से प्रभावी होने वाली नई अधिसूचनाओं के साथ छात्रों पर बोझ को कम करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 'परीक्षा पे चर्चा' (पीपीसी) सरकार की दृष्टि और प्राथमिकताओं को रेखांकित करती है। परीक्षा पे चर्चा (पीपीसी) के 7वें संस्करण के दौरान, प्रधान मंत्री मोदी ने छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत की, एक शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया जहां प्रत्येक बच्चे की अद्वितीय व्यक्तित्व को प्रोत्साहित किया जाता है और पूरी तरह से व्यक्त किया जाता है। सरकार इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए ठोस प्रयास कर रही है, यह मानते हुए कि सांस्कृतिक और सामाजिक अपेक्षाएं अक्सर छात्रों पर अनुचित दबाव डालती हैं। मोदी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की वकालत करते हुए हमें याद दिलाते हैं कि "शिक्षक नौकरी की भूमिका में नहीं हैं बल्कि वे छात्रों के जीवन को संवारने की जिम्मेदारी निभाते हैं।" तकनीकी प्रगति की तीव्र गति के साथ, सीखने की प्रक्रिया में इसे अपनाना बहुत महत्वपूर्ण है और प्रौद्योगिकी इसे सीखने के एक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए, जो हमें याद दिलाता है कि "कोई भी प्रौद्योगिकी से दूर नहीं भाग सकता," जैसा कि प्रधान मंत्री ने टिप्पणी की। सुधार आवश्यक हैं क्योंकि वे भारत को उन्नति के उच्च स्तर पर ले जा सकते हैं। समग्र दृष्टिकोण में शैक्षिक प्रथाओं को उन सिद्धांतों के साथ संरेखित करना शामिल है जो दिमागीपन और लचीलेपन को बढ़ावा देते हैं। शिक्षा में केवल बौद्धिक विकास ही नहीं, बल्कि मानव विकास का व्यापक स्पेक्ट्रम शामिल होना चाहिए। बच्चे के विकास के विभिन्न पहलुओं का आकलन और पोषण करने के लिए उचित पद्धतियों का उपयोग किया जाना चाहिए। नई शिक्षा प्रणाली व्यक्तिगत क्षमता को बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार है और यह देश की आर्थिक वृद्धि में भी योगदान देती है। यह व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है कि एक अच्छी तरह से शिक्षित आबादी आर्थिक रूप से आगे बढ़ने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हैप्रगति और सामाजिक गतिशीलता, असमानताओं को कम करना और अधिक न्यायसंगत समाज को बढ़ावा देना। इसके अलावा, शिक्षा बेहतर स्वास्थ्य, नागरिक जुड़ाव बढ़ाने और व्यक्तिगत संतुष्टि बढ़ाने में योगदान देती है। भारत की परीक्षा प्रणाली में और सुधार की आवश्यकता है। इसलिए, आगे चलकर देश में अधिक निष्पक्ष, पारदर्शी, तनाव मुक्त, लचीली और मजबूत परीक्षा प्रणाली होना तय है। सभी स्तरों पर तत्काल आधार पर छेदों को भरा जा रहा है। भारत एक मजबूत, अधिक जीवंत राष्ट्र बनाने के सही रास्ते पर है जहां प्रतिभा, ज्ञान और कौशल पनपते हैं।

सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य शैक्षिक स्तंभकार मलोट

डिजाइनिंग में करियर विकल्प : विजय गर्ग

यदि आप एक ऐसे नवोन्मेषी माहौल में काम करना चाहते हैं जहां नए विचारों को हमेशा पुरस्कृत और प्रोत्साहित किया जाता है, तो आपको रचनात्मक उद्योगों में प्रयास करना चाहिए। वर्तमान समय में डिजाइनिंग व्यवसाय मांग में हैं और बेहतरीन रचनात्मक क्षेत्र के लिए भी जाने जाते हैं। पिछले दो दशकों में, हमने डिजाइनिंग करियर में आश्चर्यजनक बदलाव देखे हैं और कला और डिजाइन की चुंबकीय दुनिया रचनात्मक लोगों के लिए विभिन्न प्रकार के करियर के अवसर प्रदान करती है। डिज़ाइनिंग में ऐसे कई करियर हैं जहां रचनात्मक लोग आगे बढ़ सकते हैं और अपने जुनून को करियर में बदल सकते हैं। डिज़ाइनिंग करियर आमतौर पर रचनात्मक और विचारों से भरे होते हैं। चूँकि डिज़ाइन कंपनियाँ, विज्ञापनदाता और प्रकाशक लगातार डिज़ाइनरों की मांग कर रहे हैं, अगले दशक में डिज़ाइन नौकरियों की संख्या 10 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। पूर्व समय में, एक स्नातक के रूप में, हम केवल कुछ भूमिकाओं तक ही सीमित रहे होंगे, लेकिन डिजाइनिंग योग्यताएं अब हमें ग्राफिक डिजाइनर से लेकर इंटीरियर डिजाइनर तक सभी प्रकार की नौकरियों के लिए तैयार करेंगी। डिजाइनिंग में करियर विकल्प आगामी पैराग्राफ में, हम विभिन्न प्रकार की डिज़ाइनिंग नौकरियों की पहचान करेंगे और उनका संक्षिप्त विवरण प्रदान करेंगे जो डिज़ाइन करियर में रुचि रखने वाले रचनात्मक लोगों के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। एक नज़र डालें और देखें कि कौन से रचनात्मक करियर में आपकी सबसे अधिक रुचि है। ग्राफ़िक डिज़ाइनरः ग्राफ़िक डिज़ाइनर सबसे अधिक मांग वाले डिज़ाइन व्यवसायों में से एक है। ग्राफिक डिजाइनरों की मुख्य भूमिका विभिन्न कंप्यूटर अनुप्रयोगों का उपयोग करके विपणन संपार्श्विक, उत्पाद चित्रण, ब्रांड पहचान और वेबसाइटों के लिए डिजाइन तैयार करना है। वे संचार समस्याओं की योजना बनाते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और दृश्य समाधान तैयार करते हैं। इसके अलावा, वे रंग, प्रकार, चित्रण, फोटोग्राफी, एनीमेशन और विभिन्न प्रिंट और लेआउट तकनीकों जैसे विभिन्न तरीकों का उपयोग करके प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और फिल्म मीडिया में संदेश पहुंचाने का सबसे प्रभावी तरीका ढूंढते हैं। इसके अलावा, ग्राफिक डिजाइनर पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, कॉर्पोरेट रिपोर्टों और अन्य प्रकाशनों के समग्र लेआउट और उत्पादन डिजाइन विकसित करते हैं। ग्राफ़िक डिज़ाइन कार्य में आवश्यक कौशल हैं; कलात्मक संवेदनशीलता, तकनीकी कौशल, संचार क्षमता, संगठन, समस्या सुलझाने की क्षमता। 12वीं पूरी करने के बाद ग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए, आपको अपनी रुचि और क्षमताओं के आधार पर एप्लाइड आर्ट, पेंटिंग, एनीमेशन या विजुअल कम्युनिकेशन या मूर्तिकला में स्नातक की डिग्री लेनी चाहिए।

भारत में, एक जूनियर ग्राफिक डिजाइनर प्रति वर्ष 6,00,000 रुपये तक कमा सकता है, जबकि एक वरिष्ठ ग्राफिक्स डिजाइनर 8,00,000 रुपये तक कमा सकता है। गेम डिज़ाइनरः डिज़ाइनिंग और एनीमेशन में करियर बनाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए गेम डिज़ाइनिंग सबसे आगामी करियर में से एक है। गेमिंग उद्योग प्रति वर्ष 50% की गति से तेजी से बढ़ रहा है। गेम डिज़ाइनर कई अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर कंसोल, पीसी और मोबाइल गेम बनाने के लिए काम करते हैं। कौशल सेट और अनुभव स्तर के आधार पर, गेम डिज़ाइन करियर में कई अलग-अलग पद उपलब्ध हैं। उन्हें गेम के स्तरों को डिज़ाइन करने और पॉप्युलेट करने के लिए गेम कंपनी द्वारा बनाए गए टूल के साथ काम करना पड़ता है। सिस्टम डिज़ाइनर कोड लिखते हैं जो गेमप्ले को नियंत्रित करता है।

लीड या वरिष्ठ डिज़ाइनर टीम के सदस्यों का प्रबंधन करते हैं और अक्सर डिज़ाइन दस्तावेज़ बनाए रखते हैं जो गेम के कथानक और कला निर्देशन से लेकर इसे बनाने के लिए उपयोग किए गए कोड तक सब कुछ कवर करते हैं। तो गेमिंग इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए आपके पास ये कौशल होने चाहिए; ड्राइंग कौशल सेट, मजबूत पारस्परिक और लिखित संचार क्षमता, संगठन टीम वर्क, विश्लेषणात्मक दिमाग, नेतृत्व कौशल, समय-प्रबंधन कौशल, वीडियो के इतिहास और रुझानों का अद्यतन ज्ञानखेल। यदि आप गेम डिजाइनर बनना चाहते हैं तो आपको चार साल का कोर्स करना होगा जैसे कंप्यूटर गेम डिजाइन एकाग्रता के साथ कंप्यूटर साइंस में बैचलर ऑफ साइंस (बीएस), गेम डिजाइन पर फोकस के साथ डिजाइन और टेक्नोलॉजी में बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। बी.एस. गेम डिज़ाइन और डेवलपमेंट में, या बी.एस. गेम डिज़ाइन में एकाग्रता के साथ कंप्यूटर विज्ञान में। ये कार्यक्रम कंप्यूटर गेम के निर्माण और डिज़ाइन और समाज के विभिन्न पहलुओं में गेम के बढ़ते उपयोग पर ध्यान केंद्रित करते हैं। प्रवेश स्तर पर एक गेम डिजाइनर का औसत वार्षिक वेतन लगभग 5,00,000 रुपये है। इंटीरियर डिजाइनरः एक इंटीरियर डिजाइनर उन जगहों के निर्माण या नवीनीकरण की योजना बनाता है, डिजाइन करता है और समन्वय करता है जहां हम रहते हैं और काम करते हैं। एक विशेषज्ञ इंटीरियर डिजाइनर एक इंटीरियर डिजाइन कर सकता है जो ग्राहक के स्वाद के लिए वैयक्तिकृत है और एक कार्यात्मक उद्देश्य प्रदान करता है। एक इंटीरियर डिजाइनर के रूप में, आप अपने डिजाइनों में सुरक्षा, यातायात प्रवाह, आराम और शैली जैसे तत्वों पर विचार करेंगे। आवश्यक कौशल जो प्रत्येक इंटीरियर डिजाइनर के पास होने चाहिए; रंग संतुलन कौशल, कोड से परिचित होना, कपड़ों का ज्ञान, शैलियों और रुझानों का ज्ञान, रचनात्मकता की भावना, अंतरिक्ष नियोजन कौशल, मजबूत कंप्यूटर कौशल। इंटीरियर डिज़ाइन में करियर के लिए इंटीरियर डिज़ाइनिंग में पेशेवर पाठ्यक्रम/डिप्लोमा/डिग्री की आवश्यकता होती है। भारत में, वरिष्ठ इंटीरियर डिजाइनरों के लिए, बोनस और कमीशन सहित वेतन सीमा लगभग 8,00,000 रुपये से शुरू होती है। एनिमेटरः एनीमेशन गतिशील छवियाँ बनाने की एक कला है। कार्य का यह क्षेत्र अलग-अलग फ्रेमों की एक श्रृंखला बनाने के बारे में है, जो तेजी से क्रम में फ़्लिक किए जाने पर छवियों को जीवंत बना देते हैं। एनिमेटर छवियों की एक विस्तृत श्रृंखला बनाते हैं जो फिल्मों, विज्ञापनों, टेलीविजन कार्यक्रमों या वीडियो गेम में देखे जाने वाले एनीमेशन का निर्माण करते हैं। वे आम तौर पर इनमें से किसी एक मीडिया में विशेषज्ञ होते हैं और आगे चलकर एक बहुत ही विशिष्ट क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, उदाहरण के लिए, पात्र, दृश्य या पृष्ठभूमि डिजाइन। पहले, एनीमेशन मैन्युअल रूप से किया जाता था; एनिमेटर एक ही क्रिया को दर्शाने के लिए कई फ्रेम बनाते हैं, लेकिन अब प्रौद्योगिकी में प्रगति के कारण वे आमतौर पर अपना काम करने के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। इस क्षेत्र के लिए आवश्यक कौशल सेट, कौशल के बारे में बात करें तो एनीमेशन करियर के लिए आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण कौशल कला और डिजाइन में वास्तविक रुचि है। यह रचनात्मक और कलात्मक अभिव्यक्ति को सामने लाएगा जो स्थिर छवियों को दृश्य ग्राफिक्स और आंदोलनों को विकसित करने की अनुमति देगा। इसके अलावा, मजबूत आईटी कौशल, विवरणों पर उच्च ध्यान और लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने की क्षमता एक कुशल एनिमेटर के अन्य गुण हैं। अधिकांश नियोक्ताओं के लिए आवश्यक है कि एनिमेटरों के पास एनीमेशन या संबंधित क्षेत्र में कम से कम स्नातक की डिग्री हो। एक अनुभवी एनिमेटर जिसके पास उत्कृष्ट एनीमेशन कार्य का एक अच्छा पोर्टफोलियो है, आसानी से प्रति वर्ष 7,00,000 रुपये तक प्राप्त कर सकता है। आर्किटेक्टः आर्किटेक्ट वे पेशेवर होते हैं जो उन जगहों को डिजाइन करते हैं जहां हम रहते हैं, काम करते हैं, खेलते हैं, सीखते हैं, खरीदारी करते हैं और खाते हैं। वे संरचनाओं के उद्देश्यों और आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिए ग्राहकों से मिलते हैं और उन्हें लागत और निर्माण समय पर प्रारंभिक अनुमान प्रदान करते हैं। वे या तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से या हाथ से स्केल किए गए चित्र तैयार करते हैं और कार्य स्थलों पर जाकर यह सुनिश्चित करते हैं कि निर्माण वास्तुशिल्प योजनाओं का पालन करता है। वे डिज़ाइन और निर्माण चित्र बनाने के लिए कंप्यूटर-एडेड डिज़ाइन और ड्राफ्टिंग (सीएडीडी) और बिल्डिंग सूचना मॉडलिंग (बीआईएम) का उपयोग करते हैं। हालाँकि, हाथ से चित्र बनाने के कौशल की अभी भी आवश्यकता होती है, विशेष रूप से किसी परियोजना के वैचारिक चरणों के दौरान और जब एक वास्तुकार किसी निर्माण कार्य में होता हैएन साइट. आर्किटेक्ट ग्राहकों को निर्माण बोलियां प्राप्त करने, ठेकेदारों का चयन करने और निर्माण अनुबंधों पर बातचीत करने में भी मदद कर सकते हैं। एक वास्तुकार बनने के लिए डिजाइन और ड्राइंग कौशल, एक व्यवस्थित, तार्किक दृष्टिकोण, विश्लेषणात्मक कौशल, उत्कृष्ट गणित कौशल, संचार और बातचीत कौशल और आईटी कौशल जैसे कौशल की आवश्यकता होगी। आर्किटेक्चर क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए आपको आर्किटेक्चर में 5 साल की स्नातक की डिग्री और कम से कम 2 साल का पेशेवर अनुभव पूरा करना होगा। एक सामान्य आर्किटेक्ट का वार्षिक वेतन पैकेज लगभग 4,50,000 रुपये है। वेब डिज़ाइनरः वेब डिज़ाइनर वेबसाइट और अन्य संबद्ध एप्लिकेशन विकसित और बनाते हैं। वेब डिज़ाइनर विभिन्न उद्योगों में और अक्सर स्वतंत्र ठेकेदारों के रूप में काम करते हैं। एक वेब डिज़ाइनर का मुख्य कर्तव्य किसी वेबसाइट का लुक, लेआउट और सुविधाएँ बनाना है। इस नौकरी में ग्राफिक डिज़ाइन और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग दोनों को समझना भी शामिल है। एक बार जब कोई वेबसाइट बन जाती है, तो एक वेब डिज़ाइनर वेबसाइट के रखरखाव और उसे जोड़ने में मदद करता है। वे साइट को अद्यतन रखने और अन्य कार्यों के साथ-साथ जरूरतों को प्राथमिकता देने के लिए विकास टीमों या प्रबंधकों के साथ सहयोग करते हैं। उनके कार्य कर्तव्यों में वेबसाइट बनाने के सभी पहलू शामिल हैं। वे ग्राहकों से मिलते हैं और उनकी जरूरतों का आकलन करते हैं। वेब डिज़ाइनर उत्पाद बनाने और बनाए रखने में मदद करते हैं। आपको आमतौर पर यह दिखाना होगा कि आपके पास विजुअल डिज़ाइन, यूएक्स (उपयोगकर्ता अनुभव), एसईओ (सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन), मार्केटिंग और सोशल मीडिया, एचटीएमएल और सीएसएसजैसे कोडिंग सॉफ़्टवेयर का उपयोग करने, फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर जैसे डिज़ाइन सॉफ़्टवेयर का उपयोग करने में कौशल है। वेब डिज़ाइनर बनने के लिए आपको मल्टीमीडिया और वेब डिज़ाइनिंग में स्नातक की डिग्री पूरी करनी होगी उसके बाद आप वेब डिज़ाइनर के रूप में अपना करियर शुरू कर सकते हैं। योग्य वेब डिज़ाइनर प्रति वर्ष लगभग 4,50,000 रुपये का औसत वेतन कमाते हैं। उत्पाद डिजाइनरः उत्पाद डिजाइनर को कभी-कभी वाणिज्यिक या औद्योगिक डिजाइनरों के साथ भी जाना जाता है। वे विनिर्मित उत्पाद बनाते हैं जो अक्सर दुनिया भर में बेचे जाते हैं। कला, इंजीनियरिंग और व्यवसाय के अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए, उत्पाद डिजाइनर उपभोक्ताओं के लिए नवीन, सुरक्षित, कार्यात्मक, स्टाइलिश उत्पाद बनाते हैं। अधिकांश एक विशिष्ट प्रकार के उत्पाद, जैसे उपकरण, चिकित्सा उपकरण, ऑटोमोबाइल, खिलौने और फर्नीचर या घरेलू सामान को डिजाइन करने में विशेषज्ञ होते हैं। उनका उद्देश्य मौजूदा उत्पादों के काम करने और दिखने के तरीके में सुधार करना और/या उन्हें कम लागत पर उत्पादित करना है। वे पूरी तरह से नए उत्पादों को डिजाइन करने में भी शामिल थे। उत्पाद डिजाइनर सहकर्मियों और ग्राहकों के साथ-साथ इंजीनियरों, मॉडल निर्माताओं, बिक्री और विपणन कर्मचारियों और अन्य कुशल लोगों के साथ मिलकर काम करने के साथ डिजाइन पर चर्चा करते हैं। वे अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए चित्र, 3-डी मॉडल और कंप्यूटर डिज़ाइन का उपयोग करते हैं। एक उत्पाद डिजाइनर को आकार और रंग पर नजर रखने वाला, विभिन्न सामग्रियों और उत्पादन विधियों को समझने वाला एक रचनात्मक व्यक्ति होना चाहिए। साथ ही, तकनीकी, व्यावहारिक और वैज्ञानिक ज्ञान और क्षमता होनी चाहिए और लोगों द्वारा उत्पादों को चुनने और उपयोग करने के तरीके में रुचि होनी चाहिए। प्रोडक्ट डिजाइनिंग में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। एक उत्पाद डिजाइनर का औसत वेतन 5,00,000 रुपये प्रति वर्ष है। फैशन डिजाइनरः फैशन डिजाइनर वे होते हैं जो मूल कपड़े, सहायक उपकरण और जूते बनाते हैं। वे डिज़ाइन स्केच करते हैं, कपड़े और पैटर्न का चयन करते हैं, और उनके द्वारा डिज़ाइन किए गए उत्पादों को बनाने के निर्देश देते हैं। वे प्रत्येक परिधान या सहायक वस्तु के लिए कपड़े, अलंकरण, रंग या शैली का चयन करते हैं और साथ ही रचनात्मक निर्देशक को डिजाइन विचार प्रस्तुत करते हैं या उन्हें फैशन या व्यापार शो में प्रदर्शित करते हैं। वे के अंतिम उत्पादन की देखरेख करते हैंउनके डिज़ाइन. इन सभी डिज़ाइनिंग उद्देश्यों के लिए, वे डिज़ाइन बनाने के लिए कंप्यूटर-एडेड डिज़ाइन प्रोग्राम का उपयोग करते हैं। फैशन डिजाइनरों में भी विशिष्ट गुण होने चाहिए जैसे; कलात्मक क्षमता, अच्छा संचार कौशल, उत्कृष्ट कंप्यूटर कौशल, रचनात्मकता, बेहतर निर्णय लेने का कौशल और विस्तार उन्मुख होना चाहिए। एक सफल फैशन डिजाइनर बनने के लिए आपके पास फैशन डिजाइनिंग में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। एक फैशन डिजाइनर प्रति वर्ष औसतन 4,50,000 रुपये वेतन कमाता है। जाहिरा तौर पर, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि कई अलग-अलग प्रकार के डिज़ाइनिंग करियर हैं जो आपको दिन-ब-दिन अपनी रचनात्मकता के स्तर का अभ्यास करने की अनुमति देंगे। अवसरों की इतनी विस्तृत श्रृंखला के साथ, आपको रचनात्मक करियर ढूंढने में सक्षम होना चाहिए जो आपके लिए आदर्श हो और आपके अभिनव दिमाग के अनुकूल हो।

सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य शैक्षिक स्तंभकार मलोट

आयकर विभाग की समिति ही बनाएगी नए कर कानूनों का मसौदा, राजस्व सचिव ने कहा- सभी हितधारकों से करेंगे विचार-विमर्श

परिवहन विशेष न्यूज

राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने बताया कि बजट में पेश किए गए आासन आयकर कानून के पहले ड्राफ्ट को टैक्स डिपार्टमेंट के इंटरनल पैनल तैयार करेगी। इससे अधिनियम को संक्षिप्त सुस्पष्ट पढ़ने और समझने में आसान हो जाएगा । भले ही पहला ड्राफ्ट इंटरनल पैनल द्वारा तैयार किया जाए मगर आगे की कार्रवाई के लिए हितधारकों से विचार-विमर्श किया जाएगा।

नई दिल्ली। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने गुरुवार को कहा कि बजट में प्रस्तावित नए सरलीकृत आयकर कानून का पहला ड्राफ्ट कर विभाग की एक आंतरिक समिति द्वारा तैयार किया जाएगा और कानून को अंतिम रूप देने से पहले हितधारकों से परामर्श किया जाएगा।

मल्होत्रा ने कहा कि यह कवायद नए डायरेक्ट कोड लाने से जुड़ी नहीं है, बल्कि आयकर कानून की व्यापक समीक्षा से जुड़ी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस सप्ताह की शुरुआत में अपने बजट भाषण में घोषणा की कि आयकर अधिनियम, 1961 की व्यापक समीक्षा छह महीने में पूरी हो जाएगी।

क्या होगा फायदा?

सीतारमण ने कहा कि इसका उद्देश्य अधिनियम को संक्षिप्त, सुस्पष्ट, पढ़ने और समझने में आसान बनाना है। इससे विवाद और मुकदमेबाजी कम होगी, जिससे करदाताओं को कर निश्चितता मिलेगी। इससे मुकदमेबाजी में उलझी मांग में भी कमी आएगी।

सीतारमण ने कहा कि इसका उद्देश्य अधिनियम को संक्षिप्त, सुस्पष्ट, पढ़ने और समझने में आसान बनाना है। इससे विवाद और मुकदमेबाजी कम होगी, जिससे करदाताओं को कर निश्चितता मिलेगी। इससे मुकदमेबाजी में उलझी मांग में भी कमी आएगी।

नहीं है कोई नई प्रत्यक्ष कर संहिता

इस सवाल पर कि क्या समीक्षा का मतलब यह होगा कि सरकार प्रत्यक्ष कर संहिता लेकर आएगी, मल्होत्रा ने कहा कि यह कोई नई प्रत्यक्ष कर संहिता नहीं है... यह एक व्यापक समीक्षा है। उन्होंने कहा कि समीक्षा के बाद सरलीकृत आयकर कानून का पहला मसौदा कर विभाग की एक आंतरिक समिति द्वारा तैयार किया जाएगा।

उद्योग चैंबर फिक्की के साथ एक संवाद सत्र में मल्होत्रा ने कहा कि हम एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहेंगे। पहला मसौदा एक आंतरिक टीम द्वारा तैयार किया जाएगा और फिर हम देखेंगे कि हितधारकों के परामर्श के साथ आगे कैसे बढ़ना है।

मिल गई है सिक्योरिटी क्लियरेंस, जल्द मिल सकती है आरबीआई से मंजूरी

IDBI बैंक ने सिक्योरिटी क्लियरेंस को पास कर लिया है और उम्मीद है कि जल्द ही RBI से इसे मंजूरी मिल जाएगी। सरकार IDBI बैंक में करीब 61 फीसदी हिस्सेदारी बेच रही है जिसके लिए वह एलआईसी की मदद ले रही है। इसमें LIC की 30.24 फीसदी और सरकार की 30.48 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। आइये इसके बारे में जानते हैं।

नई दिल्ली। IDBI बैंक के अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी कि बैंक में संभावित निवेशकों को गृह मंत्रालय से आवश्यक सुरक्षा मंजूरी मिल गई है और रिजर्व बैंक से भी जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है, । सरकार एलआईसी के साथ मिलकर IDBI बैंक में करीब 61 फीसदी हिस्सेदारी बेच रही है। इसमें भारत सरकार की 30.48 फीसदी और एलआईसी की 30.24 फीसदी हिस्सेदारी शामिल है।

जनवरी 2023 में, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) ने कहा कि उसे आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी खरीदने के लिए कई एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआई) मिले हैं। EOI के माध्यम से रुचि दिखाने वाले बोलीदाताओं को दो तरह की मंजूरी लेनी होगी । इसमें से एक सुरक्षा मंजूरी के लिए गृह मंत्रालय से और दूसरी 'उपयुक्त और उचित' मानदंडों को पूरा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से लेनी होगी।

RBI से जल्द मिलेगी मंजूरी

डेढ़ साल से अधिक समय हो गया है जब आरबीआई संभावित निवेशकों द्वारा प्रस्तुत विवरणों की जांच कर रहा है, जिसके कारण आईडीबीआई बैंक के निजीकरण की समय सीमा चूक गई है।

अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि संभावित बोलीदाताओं के लिए सुरक्षा मंजूरी पहले ही आ चुकी है। आरबीआई से भी जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है।

निवेशकों को डेटा रूम तक एक्सेस

अधिकारी ने कहा कि आवश्यक मंजूरी के बाद, निवेशकों को डेटा रूम तक पहुंच मिलेगी और उचित परिश्रम प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बीएसई पर आईडीबीआई बैंक के शेयर पिछले बंद के मुकाबले 4.70 फीसदी बढ़कर 102.12 रुपये पर कारोबार कर रहे थे।

सरकार और एलआईसी के पास आईडीबीआई बैंक में कुल 94.72 फीसदी हिस्सेदारी है, जो रणनीतिक बिक्री के बाद घटकर 34 फीसदी रह जाएगी। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में विनिवेश और परिसंपत्ति मुद्रीकरण से 50,000 करोड़ रुपये जुटाने का बजट रखा है।

अमेरिकी मार्केट में दो साल की सबसे बड़ी गिरावट, क्या किसी बड़ी अनहोनी का संकेत?

अमेरिकी शेयर बाजार में बुधवार को बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इसके बाद टेस्ला अल्फाबेट इंक एनवीडिया मेटा और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों के शेयर तेजी से फिसले हैं। अमेरिकी शेयर बाजार में यह गिरावट गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक के वित्तीय नतीजे के चलते आई है। इसके साथ ही अन्य टेक कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया के शेयर भी गिरे हैं।

नई दिल्ली। अमेरिकी शेयर मार्केट में बुधवार को पिछले दो साल की सबसे गिरावट दर्ज की गई। इसकी बड़ी दो बड़ी कंपनियों- टेस्ला और अल्फाबेट इंक के खराब वित्तीय नतीजे रहे। इससे ओवरऑल शेयर मार्केट का मिजाज खराब हुआ और एनवीडिया, मेटा प्लेटफॉर्म और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के शेयरों में भी बड़ी गिरावट आई।

क्यों गिरे अल्फाबेट और टेस्ला

गूगल की पैरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक के स्टॉक में 5.03 फीसदी की बड़ी गिरावट आई। यह तकरीबन 6 महीने में अल्फाबेट के शेयरों में दूसरी सबसे बड़ी गिरावट है। इससे पहले 31 जनवरी को इसके स्टॉक 7.5 फीसदी गिरे थे। अल्फाबेट ने टॉप और बॉटम-लाइन में बढ़त दर्ज की है, लेकिन निवेशकों चिंतित हुए Youtube ऐड रेवेन्यू को लेकर, जो उनके अनुमान से कम रहा।

वहीं, अरबपति कारोबारी एलन मस्क (Elon Musk) की ऑटोमोबाइल कंपनी टेस्ला की बात करें, तो इसके शेयरों ने 12.33 फीसदी का गोता लगाया। यह साल 2020 के बाद टेस्ला के शेयरों में सबसे बड़ी गिरावट है। इसकी वजह भी उम्मीद से कमजोर तिमाही नतीजे हैं। साथ ही, ऑटो रेवेन्यू में सालाना आधार पर 7 फीसदी की कमी आई है।

दूसरी दिग्गज कंपनियों पर भी पड़ा

अल्फाबेट इंक और टेस्ला की गिरावट ने पूरे अमेरिकी शेयर बाजार को झकझोर दिया। ब्रॉड मार्केट इंडेक्स 2.31 फीसदी घटकर 5,427.13 बंद हुआ है। वहीं, टेक-हेवी नैस्डेक (Nasdaq) ने 3.64 फीसदी का गोता लगाया और 17,342.41 के स्तर पर आ गया। डाउ जोंस इंडस्ट्रियल एवरेज की बात करें, तो यह 504.22 प्वाइंट यानी 1.25 फीसदी घटकर 39,853.87 पर बंद हुआ। यह अमेरिकी शेयर बाजार का 2022 के बाद सबसे खराब प्रदर्शन है।

दूसरी बड़ी टेक कंपनियों के शेयरों ने अल्फाबेट और टेस्ला से हमदर्दी दिखाई। उनके शेयरों में भी बड़ी गिरावट दिखी। पिछले पांच साल में करीब ढाई हजार फीसदी का रिटर्न देने वाली एनवीडिया का शेयर 6.8 फीसदी घटा। मार्क जुकरबर्ग का मेटा प्लेटफॉर्म्स भी 5.6 फीसदी गिरा, जिसके पास फेसबुक, इंस्टाग्राम और वॉट्सऐप का मालिकाना हक है। माइक्रोसॉफ्ट के शेयरों में भी 3.6 फीसदी की गिरावट आई।

5 फीसदी से ज्यादा गिरा एक्सिस बैंक का शेयर, ब्रोकरेज ने टारगेट प्राइस में किए बदलाव

परिवहन विशेष न्यूज

एक्सिस बैंक के शेयरों में गुरुवार को 5 फीसदी से अधिक की बड़ी गिरावट आई। इसके वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही के नतीजे उम्मीद से काफी कमजोर रहे। इससे निवेशकों ने एक्सिस स्टॉक्स में जमकर बिकवाली की। ब्रोकरेज ने भी एक्सिस बैंक की रेटिंग और टारगेट प्राइस में अहम बदलाव किए हैं। आइए जानते हैं कि क्या अब एक्सिस बैंक के शेयर खरीदने में फायदा है।

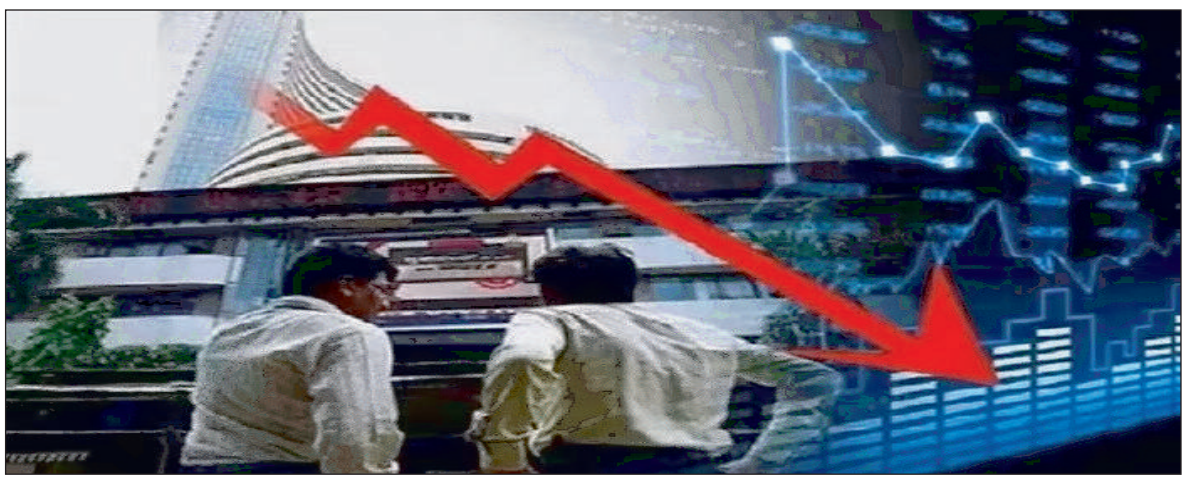

नई दिल्ली। प्राइवेट सेक्टर के लेंडर एक्सिस बैंक के स्टॉक में गुरुवार को जबरदस्त बिकवाली दिखी। इसके शेयर कारोबार के दौरान एक वक्त करीब 7 फीसदी तक फिसल गए थे। इस गिरावट के झटके से स्टॉक दिनभर नहीं उबर पाया। आखिर में यह BSE 5.19 फीसदी की गिरावट के साथ 1175.35 रुपये के भाव पर बंद हुआ।

एक्सिस बैंक के शेयर में क्यों आई गिरावट?

एक्सिस बैंक के वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही के नतीजे उम्मीद से काफी कमजोर रहे। जून तिमाही में एक्सिस बैंक का नेट प्रॉफिट 6,035 करोड़ रुपये रहा। सालाना आधार पर यह 4 फीसदी अधिक रही, लेकिन मुनाफे की ग्रोथ उम्मीद से कम रही। ब्याज से कमाई में 18 फीसदी उछाल आया और यह 25,557 करोड़ रुपये तक गई।

एक्सिस बैंक पर ब्रोकरेज का रुख

सिटी ने एक्सिस बैंक की रेटिंग डाउनग्रेड कर दी है। पहले उसने बैंक के लिए Buy रेटिंग दी थी, जिसे बदलकर अब न्यूट्रल कर दिया। टारगेट प्राइस भी घटाकर 1370 रुपये से 1320 रुपये कर दिया है। सिटी का कहना है कि एक्सिस बैंक की एसेट क्वालिटी कमजोर हुई है। साथ ही, ग्रोथ और RoA में भी सुस्ती है।

वहीं, ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म बर्न्स्टीन ने एक्सिस बैंक की आउटपरफॉर्म रेटिंग बरकरार रखी है। उसने 1420 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। Nuvama ने भी एक्सिस बैंक की अपनी Buy रेटिंग में कोई बदलाव नहीं किया। हालांकि, उसने टारगेट प्राइस 1500 रुपये से घटाकर 1430 रुपये कर दिया। नोमुरा ब्रोकरेज ने भी एक्सिस बैंक के लिए टारगेट प्राइस 1485 रुपये से घटाकर 1435 रुपये कर दिया है।

एक्सिस बैंक के शेयर का हाल

एक्सिस बैंक में पिछले एक महीने से सुस्ती है और इस दौरान उसने 7.49 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीने में एक्सिस बैंक के स्टॉक से निवेशकों को 13 और एक साल में 22 फीसदी का मुनाफा हुआ है।

अब देश छोड़कर भाग नहीं पाएंगे काला धन वाले, ब्लैक मनी एक्ट के तहत लेना होगा क्लीयरेंस सर्टिफिकेट

23 जुलाई को देश में पूर्ण बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने बजट भाषण के साथ कई बड़े एलान किए हैं। नए एलानों के साथ अब काला धन यानी ब्लैक मनी वाले लोग आसानी से देश छोड़कर नहीं भाग सकेंगे। देश छोड़ कर जाने वाले के लिए नियम सख्त कर दिए गए हैं।

नई दिल्ली। 23 जुलाई को देश में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पूर्ण बजट पेश किया गया है। इसी के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े एलान किए हैं। इसी कड़ी में बजट में भारत से बाहर जाते समय आवश्यक क्लीयरेंस सर्टिफिकेट से जुड़े प्रावधानों को कड़ा कर दिया गया है। नए नियमों के मुताबिक, वे भारतीय जो भारत छोड़कर जा रहे हैं, उनके लिए ब्लैक मनी एक्ट के तहत क्लीन चिट देने वाला क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जरूरी होगा। हालांकि, यह नया नियम 1 अक्टूबर से लागू हो रहा है।

वर्तमान में क्या है व्यवस्था

वर्तमान में, भारत से बाहर जाने के लिए आयकर (आई-टी) अधिनियम की धारा 230 के तहत कर अधिकारियों से प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना जरूरी है। इस प्रमाण पत्र के जरिए साफ होता है कि देश छोड़कर जाने वालों पर कोई बकाया या देनदारी नहीं है और ऐसे लोगों ने बकाए का भुगतान करने के लिए संतोषजनक व्यवस्था की है।

किन लोगों के लिए जरूरी होगा सर्टिफिकेट

यह आईटी एक्ट के तहत आने वाले टैक्स, उपहार कर अधिनियम और व्यय कर अधिनियम पर लागू होता है। इस तरह का प्रमाणपत्र उन स्थितियों में जरूरी होगा जब आयकर प्राधिकरण की राय में किसी व्यक्ति के लिए इसे प्राप्त करना जरूरी होगा। कर विशेषज्ञों का मानना है कि अधिसूचना या उसके बाद आने वाले नियम आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझाएंगे।

बिजली-पानी, गैस कनेक्शन के बिल से आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट हो जाएगा; बस 3 महीने हो पुराना

आधार कार्ड में पते को अपडेट करवाने की जरूरत है लेकिन यह समझ नहीं आ रहा है कि कौन-से डॉक्युमेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए तो ये आर्टिकल आपकी परेशानी को कम कर सकता है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण आधार कार्ड होल्डर को खुद इस बारे में जानकारी देता है कि आधार में एड्रेस का प्रमाण कौन-से डॉक्यूमेंट बन सकते हैं और कौन-से डॉक्यूमेंट नहीं।

नई दिल्ली। आधार कार्ड भारतीय नागरिकों की पहचान से जुड़ा डॉक्युमेंट है। इस सरकारी डॉक्युमेंट का इस्तेमाल पहचान से जुड़े कामों में होता है। यही वजह है कि आपकी यह सरकारी आईडी अप-टू-डेट होनी चाहिए। यानी आधार कार्ड में दी गई सारी जानकारियां पुरानी नहीं होनी चाहिए। आधार कार्ड में आपके नाम और पते जैसी जानकारियां सही होनी चाहिए। अगर आप भी आधार कार्ड में एडरेस को अपडेट करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो इसके लिए इस्तेमाल होने वाले डॉक्युमेंट्स की जानकारी होना जरूरी है।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की ऑफिशियल वेबसाइट पर यह साफ किया गया है कि आधार कार्ड होल्डर किन दस्तावेजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस आर्टिकल में इसी को लेकर जानकारी दे रहे हैं।

कौन-से डॉक्युमेंट बनेंगे पते का सबूत

आधार कार्ड में पता अपडेट करवाने के लिए आप वैध भारतीय पासपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि, अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपने पैन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं तो ऐसा नहीं होगा। पैन कार्ड आपके पते का सबूत नहीं माना जाएगा। इसी तरह ड्राइविंग लाइसेंस आपके पते का सबूत नहीं बन सकता है लेकिन, राशन और ई-राशन कार्ड पते का सबूत माना जाएगा।

बिजली, पानी और टेलीफोन बिल का कर सकते हैं इस्तेमाल

आधार कार्ड में पता अपडेट करवाने के लिए आप बिजली के बिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि, आपके बिजली का बिल 3 महीने पुराना होना चाहिए। इसी तरह अगर आपके घर में टेलीफोन का इस्तेमाल होता है तो टेलीफोन लैंडलाइन बिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह भी 3 महीने पुराना होना चाहिए।

इसी तरह अगर आप पोस्टपेड मोबाइल बिल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का कहना है कि आधार कार्ड होल्डर अपनी जीवन और चिकित्सा बीमा पॉलिसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि, यह पॉलिसी जारी करने की तारीख से 1 वर्ष तक ही मान्य होगा।

कस्टम ड्यूटी घटने के बाद लगातार कम हो रहे सोना-चांदी के दाम, खरीदने का सुनहरा मौका

परिवहन विशेष न्यूज

गुरुवार को सोना 1000 रुपये गिरकर 70650 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार बुधवार को पिछले सत्र में गोल्ड की कीमत 71650 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। चांदी की कीमत भी 3500 रुपये की भारी गिरावट के साथ 84000 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। पिछले सत्र में यह 87500 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी।

नई दिल्ली। विदेशी बाजारों में कीमतों में गिरावट के कारण आभूषण विक्रेताओं की भारी बिकवाली के बीच स्थानीय बाजार में गुरुवार को सोने की कीमतों में तीसरे दिन भी गिरावट जारी रही। वहीं, चांदी की कीमतों में भी गिरावट देखी गई।

लगातार घट रही साने की कीमत

गुरुवार को सोना 1,000 रुपये गिरकर 70,650 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, बुधवार को पिछले सत्र में गोल्ड की कीमत 71,650 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। राष्ट्रीय राजधानी में तीसरे दिन भी गिरावट जारी रही, 99.9 प्रतिशत और 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत 1,000-1,000 रुपये गिरकर क्रमशः 70,650 रुपये प्रति 10 ग्राम और 70,300 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई।

चांदी भी हुई सस्ती

चांदी की कीमत भी 3,500 रुपये की भारी गिरावट के साथ 84,000 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। पिछले सत्र में यह 87,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। 23 जुलाई से पिछले तीन सत्रों में सोने की कीमत में 5,000 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट आई है। 23 जुलाई को सोने की कीमत 3,350 रुपये घटकर 72,300 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई थी। यह इस साल की सबसे बड़ी गिरावट है।

ग्लोबल मार्केट का हाल

वैश्विक स्तर पर कॉमेक्स सोना 42.20 डॉलर प्रति औंस की गिरावट के साथ 2,421.80 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। सरकार ने मंगलवार को सोने और चांदी सहित कई उत्पादों पर सीमा शुल्क में कटौती का फैसला किया था। सोने और चांदी पर सीमा शुल्क 15 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत कर दिया गया है। व्यापारियों ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कमजोरी के रुख के बीच स्थानीय आभूषण विक्रेताओं की लगातार बिकवाली से सोने की कीमतों में गिरावट आई।

सीरवी संस्थान उदयपुर छात्रावास का हुआ भूमि पूजन

बोलियों में दश नये कमरो व लाखों की हुई घोषणा

परिवहन विशेष न्यूज

उदयपुर - पर्यटक नगरी उदयपुर बेडवास में स्थित आशापुरा माताजी कोलोनी उदयपुर में सोमवार को सीरवी छात्रावास का भूमि पूजन कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। धर्मगुरु पिरोसा गोपालसिंह परमार बिठुडापिरान एवं सद्गुरु भंवर महाराज नारलाई धाम के पावन सानिध्य व मोहनसिंह वरपा देवली पाबुजी की अध्यक्षता एवं समाज बंधुओं, समाज की विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारियों, दानवीर भामाशाहो, माता बहनों, विद्यार्थियों की उपस्थिति में बनने जा रहे सीरवी छात्रावास उदयपुर का भूमि पूजन का कार्यक्रम सीरवी समाज उदयपुर व सम्पूर्ण देश से पधारे 800-900 समाज बंधुओं की उपस्थिति में बहुत ही सफल, उद्देश्यपूर्ण, अकल्पनीय अविश्वसनीय सम्पन्न हुआ। पर्यटन व शैक्षणिक नगरी उदयपुर में शिक्षा मंदिर की नींव संत सानिध्य व भूमि पूजन की शिलाओं के बोलीदाता भामाशाह बंधुओं के कर कमलों से किया गया। समारोह की शुरुआत माँ आईजी के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर व माताजी की आरती से हुई। संस्था के सरक्षंक रामलाल सैणचा ने स्वागत किया ।इसके बाद संस्थान के अध्यक्ष खीवराज परमार द्वारा पधारे अतिथियों, समाज बंधुओं के स्वागत भाषण, सचिव दौलाराम सोलंकी द्वारा छात्रावास की महता पर प्रकाश डाला। इस भूमि पूजन कार्यक्रम में समाज बंधुओ ने बढ़ - चढ़ कर बोलियां में भाग लिया और बोलियां में ही लाखों रुपये की घोषणा हुई, इसके साथ ही करीब 10 नए कमरों की घोषणा और 20 आजीवन सदस्यों ने अपना नाम लिखवाया। इस कार्यक्रम में सभी मेहमानों ने बहुत ही अच्छा सहयोग किया और सब में छात्रावास बनाने के प्रति जोश उत्साह भरपूर देखने को मिला। इस कार्यक्रम में कमरों के बोलीदाता और हॉल, किचन के भामाशाहो, समाज की वडेरो, विभिन्न संस्थाओं से पधारे पदाधिकारियों का साफा पहनाकर स्वागत किया गया। मंच का संचालक घीसाराम सीरवी बिजोवा, प्रेमजी सीरवी नवागुड़ा, भजन गायक भंवरलाल सीरवी हैदराबाद तीनों बहुत ही तालमेल के साथ मंच को संभाला और बोलियों में भामाशाह को प्रेरित किया। इस मौके पर पूनाराम मुलेवा गुड़ा रूपसिंह, रामलाल सैणचा रामपुरा, सीए. चुन्निलाल लच्छेटा धनला, किशोर पंवार बाडसा, टीकमराम पंवार चौधरियो की ढाणी, दिनेश गेहलोत अध्यक्ष महाराष्ट्र प्रांत, रामलाल सोलंकी गुडा केसरसिंह, गेनाराम सोलंकी गुडाएंदला, खंगारराम देवड़ा राणावास, मांगीलाल मुलेवा पाबूजी देवली, रमेश कुमार सूर्या इलेक्ट्रॉनिक्स पुणे, भरतकुमार चोयल अध्यक्ष बाली नगरपालिका, पूनमराम पंवार बाडसा, नेमीचंद परिहार अध्यक्ष जवाली विद्यापीठ, मध्य प्रदेश से डॉ. दिनेश सतपुडा, पृथ्वीसिंह, मदनसिंह सिंदरा जयपुर, वरदाराम इटेन्द्रा चारणान एडवोकेट जोधपुर, धन्नाराम गेहलोत बाली, हीरालाल राठौड़ बिबवेवाड़ी अध्यक्ष, हीरालाल पंवार सूरत, ओखाराम सोलंकी ईसाली, भंवरलाल काग मंडिया पाली, भुराराम जाणुदा, केसाराम संगारेड्डी, भूराराम बुसी महासचिव प्रदेश समिति राजस्थान, हिम्तराम सोलंकी देसुरी सहित समाज के अनेक गणमान्य उपस्थित रहे।

शैक्षणिक गतिविधियों में संगम विश्विद्यालय राजस्थान में अग्रणी: प्रो.करुणेश सक्सेना

आई.आई.आर.ऍफ़ रैंकिंग में भारत में सेतिसवां और राजस्थान में तीसरा स्थान के गौरव से गौरवान्वित संगम विश्वविद्यालय

परिवहन विशेष अनूप कुमार शर्मा

भिलवाड़ा संगम विश्वविद्यालय भीलवाड़ा के द्वारा सत्र 2023 24 में बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की गई है। इसी क्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर करुणेश सक्सेना ने प्रेस वार्ता में संबोधित करते हुए बताया की भारत के आई.आई.आर.ऍफ़ रैंकिंग में सेतिसवां और राजस्थान में तीसरा स्थान के गौरव से गौरवान्वित संगम विश्वविद्यालय अब सभी क्षेत्रों में कार्यक्रम में राजस्थान का सिरमौर बन गया है ।

नवीन कोर्सः नए सत्र से बीएससी नर्सिंग तथा बीएससी जीएनएम कोर्स को इसी सत्र 2024–25 से मान्यता दी गई है।अब भीलवाड़ा के छात्र छात्राएं सभी सुख सुविधा एवं विकल्पों से पूर्ण लैब,100 बेड हॉस्पिटलआदि में नर्सिंग की ट्रेनिंग विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर सकेंगे।संगम विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में विश्वस्तरीय पाठ्यक्रम जैसे फिजियोथेरेपी,शिक्षा प्रौद्योगिकी में एमए,शिक्षा नेतृत्व में पीजी डिप्लोमा,गाइडेंस और काउंसलिंग में डिप्लोमा , संगम ग्रुप द्वारा सपोर्टिंग टैक्टाइल डिप्लोमा जैसे पाठ्यक्रम इस नवीन सत्र 2024-25 से प्रारम्भ किये जा रहे हैं ।

अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन सेवाओं (आईसीएस) से आईएसओ 21001: 2018 और आईएसओ 14001: 2015 प्राप्त हुआ।आईएसओ 2100:2018, शैक्षिक संगठनों की प्रबंधन प्रणाली पर केंद्रित है और सभी शिक्षण-अधिगम पहलुओं और अन्य लाभार्थी आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को कवर करता है, यह पर्यावरण प्रबंधन के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानक है।

राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय एमओयूः

मलेशिया की प्रमुख दो बड़ी यूनिवर्सिटी से एम ओ यू,दुबई,वियतनाम,बांग्लादेश के विश्वविद्यालय से एमओयू आदि किया गए है।खेलकूद,एनसीसी, एनएसएसः2023-24 में खेल कूद प्रतियोगिता में उत्कृष्ठ प्रदर्शन रहा ।विश्विद्यालय ने अखिल भारतीय अंतर विश्विद्यालय , दक्षिण-पश्चिम अंतर विश्विद्यालय एवम पश्चिम क्षेत्र अंतर विश्विद्यालय की विभिन्न खेलो में कुल 22 खेलो में भाग लिया जिसमे कुल 197 खिलाड़ियों ने संगम विश्विद्यालय का प्रतिनिधित्व किया।एनसीसी कैडेट यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम नेपाल में चयन,कई राष्ट्रीय शिविर जैसे थल सेना शिविर, ईबीएसबी,ट्रेकिंग कैंप,राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में चयन आदि हुआ है। एनएसएस के विद्यार्थियों ने नेशनल यूथ फेस्टिवल नासिक में राजस्थान दल का प्रतिनिधित्व किया है। संगम विश्वविद्यालय के तीन एनएसए राजस्थान दलराष्ट्रीय शिविरो में श्रेष्ठता दिखाई है।

विश्वविद्यालय के बीटेक छात्र स्वर्णिम माहेश्वरी ने एनपीटीईएल परीक्षा में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है।

कामकाजी पेशेवरों को सशक्त बनाने और उनके निरंतर विकास को बढ़ावा देने के लिए, संगम विश्वविद्यालय द्वारा एमडीपी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है।हमारा लक्ष्य सैद्धांतिक ज्ञान और व्यावहारिक अनुप्रयोग के बीच अंतर को पाटना है। इस तरह के एमडीपी उनके दैनिक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण हैं।

भारतीय ज्ञान प्रणाली (आईकेएस), मानव मूल्यों और नैतिकता, प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान के तत्वों को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। यूजीसी का आदेश है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में 5% पाठ्यक्रम में आईकेएस शामिल होना चाहिए। इस प्रयास का उद्देश्य पारंपरिक और समकालीन ज्ञान का मिश्रण करना, समग्र शैक्षिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर गर्व को बढ़ावा देना है। संगम विश्वविद्यालय ने भारतीय ज्ञान प्रणाली पर पाठ्यक्रम शामिल करने वाला

पहला विश्वविद्यालय बनकर शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी कदम उठाया है।भारत सरकार द्वारा संगम विश्वविद्यालय को 4.33 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट स्वीकृत,क्षेत्र के युवाओं को तकनीकी स्टार्टअप्स हेतु 10 लाख रुपये तक का अनुदान मिलेगा।विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), भारत सरकार से संगम विश्वविद्यालय, भीलवाड़ा के समावेशी तकनीकी इन्क्यूबेशन सेंटर (संगम आई-टीबीआई) को चार करोड़ तेंतीस लाख रुपये के प्रोजेक्ट की अनुशंसा की गयी है।पिछले सत्र में लगभग देश की 80 कंपनियों ने विश्वविद्यालय में छात्र-छात्राओं को रोजगार दिया है तथा लाखों के पैकेज पर चयन हुआ है।अकादमिक गुणवत्ता में श्रेष्ठ संगम विश्वविद्यालय,समस्त डिग्री,डिप्लोमा डिग्री भारत सरकार के डीजी लाकर पर उपलब्धःदसवां दीक्षांत समारोह तक प्रदान की गई विश्वविद्यालय की समस्त ग्रेडशीट, डिग्री ,डिप्लोमा डिग्री ,सर्टिफिकेट कुल 3376 भारत सरकार के डिजिटल लॉकर में अपलोड की जा चुकी है जो विद्यार्थियों के लिए डिजिटल उपलब्ध रहेगी।

एल्युमिनाई एसोसिएशन मीट संपन्न- अहमदाबाद चैप्टर का उद्घाटन हुआ जिससे आपस में छात्र संघटन मजबूत होगा।अन्य आयोजनःपहली बार माइक्रो कोर्स की अवधारणा शुरू की जिसमे "ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग और कन्वेयन्सिंग"पर छह सप्ताह के माइक्रो कोर्स का ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित किया गया।एनईपी 2020 (राष्ट्रीय शिक्षा नीति) के कार्यान्वयन पर कार्यशाला का आयोजन,शोध कार्यशाला,राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता का आयोजन, एच आर कॉन्क्लेव जयपुर,छात्रों का अहमदाबाद में प्रतिष्ठित अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (इसरो)का ज्ञानवर्धक और समृद्ध भ्रमण,बुजुर्गों की समस्याओं पर दो दिवसीय क्षेत्रीय संगोष्ठी का आयोजन,कॉमन सेन्स विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन ,हाईफ्लायर प्रबंध प्रशिक्षण कार्यक्रम

स्टूडेंट क्लब सोसायटीःसंगम विश्वविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों हेतु विभिन्न सोसाइटी एवं क्लब जैसे कल्चरल सोसायटी,टेक्निकल सोसाइटी, प्रोफेशनल सोसाइटी , लिटरेरी सोसाइटी ,सोशल एंड ग्रीन सोसाइटी,फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी बनाए गए है।

कुलपति प्रोफ़ेसर करुणेश सक्सेना ने बताया की "भारत ही नहीं अपितु सम्पूर्ण विश्व आज शिक्षा के क्षेत्र में नित नयी चुनौतियों से जूझ रहा है ,अतःइस स्थिति में शिक्षाविदों को शिक्षा के क्षेत्र में नवचार करना अत्यन्त आवश्क हो जाता है"

प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर मानस रंजन पानीगाही ने बताया कि संगम विश्वविद्यालय ने शोध में एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त करी है जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालय की फैकल्टी ने 100 से अधिक पेटेंट पब्लिश किए है।नए पाठ्क्रम से विद्यार्थी शिक्षा क्षेत्र में शैक्षणिक, प्रशासनिक और प्रबंधकीय पेशेवरों को शैक्षिक नेतृत्व के महत्वपूर्ण आयामों को समझने और कौशल, दक्षता दृष्टिकोण विकसित करने के लिए तैयार हो जाता है , जो शिक्षा जगत में मुखिया के रूप में सशक्त बना सकता है ताकि वे अपने संस्थानों और संगठनों को मजबूत कर सकें और समाज को विकास की ओर ले जाने के लिए शिक्षा प्रणाली को बदलने के लिए नए रास्ते प्रशस्त कर सकें । ₹एन ई पी 2020₹ के विशेष संदर्भ में शैक्षिक समाज की वर्तमान आवश्यकताओं को क्रियान्वित करना है। रजिस्ट्रार प्रो राजीव मेहता ने अंत में सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया तथा सभी संपादक ,पत्रकारों को विश्वविद्यालय का इन्फ्रास्ट्रक्चर परिवर्तन को बताया।

भोपाल जिले में धारा - 163 (1) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

25 जुलाई पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल हरिनारायणाचारी मिश्र ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा - 163 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रतिबंधात्मक आदेश किये हैं।

1. समस्त प्रकार के आयोजनों जैसे- धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, जूलुस, रैली, आमसभा, पुतला दहन, पद यात्रा, रथ यात्रा, वाहन रैली, ज्ञापन, कार्यालय, निवास व शासकीय भवन का घेराव आदि के आयोजन के लिए पुलिस उपायुक्त, आसूचना एवं सुरक्षा, नगरीय पुलिस भोपाल से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा, बिना अनुमति प्राप्त किये आयोजित होने वाले आयोजनों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी। साथ ही ऐसे आयोजित कार्यक्रमों में अव्यवस्था एवं कानून व्यवस्था के दौरान होने वाली क्षति/क्षतियां (Damages) की जिम्मेदारी भी आयोजकों की होगी।

2. अनुमति पत्र में दी गई सभी शर्तों का पालन करना, करवाना बाध्यकारी होगा।

3. यदि किसी समुदाय, संगठन, राजनैतिक दलों, समिति, प्रतिनिधि मण्डल एवं आयोजकों द्वारा किसी सार्वजनिक स्थल, शासकीय परिसर, शासकीय कार्यालय, भवन अथवा किसी भी सरकारी संपत्ति को अपने कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार से क्षति पहुंचाई जाती है तो इस प्रकार के कृत्यों के लिए कार्यक्रम के आयोजकों की जिम्मेदारी होगी तथा उनके विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जा सकेगी।

यह आदेश सर्वसाधारण को संबोधित है और चूंकि वर्तमान परिस्थितियों में जन-साधारण को इसकी सूचना समयाभाव के कारण देना संभव नहीं है। अतः भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2) के अंतर्गत एक पक्षीय आदेश पारित किया जाता है।

इंडिगो फ्लाइट में आई तकनीकी खराबी, 10 घंटे तक फंसे रहे बच्चे-बुजुर्ग समेत 200 यात्री

इंडिगो की फ्लाइट में अचानक तकनीकी खराबी आने से यात्रियों को घंटों तक परेशानी झेलनी पड़ी। इन यात्रियों में बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं। इंडिगो की ओर से बताया गया कि जांच के बाद विमान को रवाना कर दिया गया। हालांकि करीब दस घंटे तक यात्री एयरपोर्ट पर ही फंसे रहे। जानिए आखिर पूरा मामला क्या है?

नईदिल्ली। इस्तांबुल से नई दिल्ली आ रहे इंडिगो के एक विमान में तकनीकी खराबी आ गई। जिस वजह से विमान समय से उड़ान नहीं भर पाया। वहीं, इंडिगो की ओर से बताया गया कि जांच के बाद विमान को रवाना किया गया।

10 घंटे तक फंसे रहे 200 यात्री

बताया गया कि विमान में 200 से ज्यादा यात्री जाने हैं, जिनमें बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं। 10 घंटे से ज्यादा समय से यात्री (इस्तांबुल एयरपोर्ट) पर फंसे हुए हैं। बता दें कि नई दिल्ली जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट बुधवार को 20:00 बजे उड़ान भरने वाली थी। लेकिन विमान में तकनीकी खराबी आने से यात्री समय से अपने गंतव्य की ओर नहीं जा सके। इस दौरान एयरपोर्ट पर यात्रियों में काफी गहमा-गहमी का माहौल रहा।

इंडिगो ने यात्रियों को दी जानकारी

इंडिगो की ओर से कहा गया कि विमान में तकनीकी खराबी के कारण इस्तांबुल से दिल्ली जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6E 12 में देरी हुई। यात्रियों को देरी के बारे में बताया दिया गया है। साथ ही उन्हें जलपान परोसा गया और एयरपोर्ट पर प्रतीक्षा समय को कम करने के लिए तुरंत जरूरी इंतजाम किए गए। इंडिगो की ओर से बताया गया कि जरूरी जांच के बाद उसी विमान को गंतव्य के लिए रवाना किया गया।

भलस्वा की डेरियां चार सप्ताह में हों स्थानांतरित, हाईकोर्ट ने कहा- मंजूरी प्रक्रिया पूरी कर जरूरी कदम उठाए डूसिब

भलस्वा की सभी डेरियों को स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने डूसिब को चार सप्ताह में मंजूरी प्रक्रिया पूरी कर जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने MCD और डूसिब को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि मदनपुर खादर और घोघा डेरी कॉलोनी सहित सभी डेरी कॉलोनियों में सभी अनधिकृत निर्माण हटा दिए जाएं। पढ़िए पूरा मामला क्या है?

नईदिल्ली। चार सप्ताह के अंदर भलस्वा से सभी डेरियों को घोघा डेरी कॉलोनी में स्थानांतरित करने का आदेश देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिकारियों को राष्ट्रीय राजधानी में सभी डेरी कालोनियों से अनधिकृत निर्माण हटाने का निर्देश दिया है।

अदालत ने दिए ये निर्देश

भलस्वा और गाजीपुर डेरियों के पास दुधारू मवेशियों को कचरा खाने से रोकने के लिए कार्रवाई करने में एमसीडी और दिल्ली सरकार के अधिकारियों की अक्षमता को देखते हुए अदालत ने भलस्वा डेरी कॉलोनी को स्थानांतरित करने का आदेश दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन व न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने कहा कि इस दलील में दम है कि भलस्वा डेरी कॉलोनी को स्थानांतरित करने के लिए 30 एकड़ भूमि की जरूरत है और घोघा डेरी कॉलोनी में 83 एकड़ की अप्रयुक्त भूमि उपलब्ध है। ऐसे में भलस्वा की सभी डेरियों को एमसीडी समेत अन्य एजेंसियों को घोघा कॉलोनी स्थानांतरित करने का निर्देश देते हैं।

डूसिब चार सप्ताह में उठाए जरूरी कदम

पीठ ने कहा कि दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब), दिल्ली सरकार मंजूरी की प्रक्रिया को पूरा करके चार सप्ताह में इसके लिए जरूरी कदम उठाए। डेरी कॉलोनियों में अनधिकृत निर्माण के संबंध में अदालत ने एमसीडी और डूसिब को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि मदनपुर खादर और घोघा डेरी कालोनी सहित सभी डेरी कॉलोनियों में सभी अनधिकृत निर्माण हटा दिए जाएं। अदालत ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि भूखंड को अपनी मूल स्थिति में वापस लाया जाए, ताकि इन कॉलोनियों में मवेशियों के लिए आवंटन किया जा सके। अदालत ने उक्त आदेश दिल्ली में डेरियों की स्थिति के संबंध में याचिकाकर्ता सुनयना सिब्बल की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।

श्रावण मास के पवित्र महीने में कानून व्यवस्था तथा सफाई व्यवस्था को लेकर जिला कलेक्टर श्री शेखावत ने जारी किया आदेश

परिवहन विशेष अनूप कुमार शर्मा

शाहपुरा। जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत के निर्देशानुसार श्रावण मास के पवित्र महीने में एवं विशेष रूप से माह के प्रत्येक सोमवार को दर्शनार्थियों का धार्मिक स्थलों पर बड़ी संख्या में आवागमन को देखते हुए तथा वहां आयोजित होने वाले भजन कीर्तन, यात्रा, भोजन प्रसादी इत्यादि कार्यक्रमो में कानून व्यवस्था एवं सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कानून व्यवस्था एवं सफाई व्यवस्था पर पूर्ण निगरानी रखी जाने और विशेष सतर्कता बरती जाने के संबंध में सम्बन्धित ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय को पाबन्द किया गया है।

जिला कलेक्टर शेखावत के आदेशानुसार संबंधित क्षेत्र के एस डी एम तथा पुलिस अधिकारी द्वारा सम्बन्धित मंदिर प्रबन्धन कमेटी, पुजारी से भी सम्पर्क स्थापित कर इस दौरान आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करवाई जाएंगी।

सम्बलपुर पुरी इंटरसिटी एक्सप्रेस को सही टाइम चलना और एक नयी रेल चलाने की मांग

मनोरंजन सासमल , स्टेटे हेड उडीशा , भुबनेस्वर् : संबलपुर पुरी इंटरसिटी से आने-जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह ट्रेन एक से दो घंटे तक की देरी से चल रही है । जिससे सभी यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है । राजधानी पहुँचते-पहुँचते साढ़े बारह बजे जाते हैं । जब तक आप ऑफिस पहुंचते हैं, ऑफिस का लंच ब्रेक हो जाता है। कर्मचारी खाना खाकर 4:30 से 4:30 बजे तक ऑफिस आ रहे हैं और ट्रेन छूटने का समय हो जाते है ।कुछ काम नहीं होते हैं। बस ट्रेन का किराया देना और खर्च करना है ।सम्बलपुर यात्रियों का यात्रा करने के लिए 18303/18304 इंटरसिटी ट्रेन की केंद्र सरकार ने चलाया था ।सम्बलपुर लोगों ने एक दिन मे भुबनेश्वर जा के काम निपटाके आ सकते थे , अबी ये ट्रेन सफर कोई काम का नहीं ।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023